www.tamsasanket.com
वर्षः 29 || अंक 217 || अम्बेडकरनगर
शुक्रवार
30 अक्टूबर 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:14
सूर्यास्तः 05:25
अधिकतमः 24°00
न्यूनतमः 21°00

पेज 07

विशेष समाचार | जियो की छलांग और विकसित ... >> पेज 04 | आगरा मे 59 निजी विद्यालयों... >> पेज 06 | तमन्ना ने अन्नू कपूर के कमेंट ...

सीजेआई बोले- अगर उनकी लापरवाही तो हर्जाना दें, 2026 में ₹800 करोड़ से ज्यादा की ठगी

बैंक डिजिटल अरेस्ट की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते

चिंता

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर गुरुवार को चिंता जताई। कहा कि जागरूकता अभियान और लगातार खबरें आने के बावजूद शिक्षित लोग भी इन घोटालों का शिकार कैसे हो रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमेंट किया, 'अगर बैंक की लापरवाही के कारण साइबर ठगी होती है तो बैंक पीड़ित को मुआवजा दें और जिम्मेदारी तय होने पर कार्रवाई का सामना करें। यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम आदेश नहीं।' 2026 में देश में डिजिटल अरेस्ट के 22 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए। साइबर अपराधियों ने लोगों से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। वहीं, 2025 में डिजिटल अरेस्ट के 58,239 केस सामने आए थे और करीब 1211 करोड़ रुपए की रकम ठगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में अलग अपराध घोषित करने और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने पर विचार करने को कहा। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह भी कहा कि ठोस सबूत मिलने पर आरोपियों की संपत्ति फ्रीज की जा सकती है। साइबर सुरक्षा कंपनी आर्कटिक वुल्फ के मुताबिक, त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल पेमेंट और ट्रैवल बुकिंग बढ़ने से साइबर ठगी का खतरा बढ़ सकता है।

>> (शेष पेज 06 पर)

एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने बताया कि हाल ही में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के डर से लोग मानसिक दबाव में आकर ठगों के निर्देश मान लेते हैं और अपनी जमा-पूंजी गंवा बैठते हैं।

देश में डिजिटल अरेस्ट के 5 बड़े मामले

1. **मुंबई: बुजुर्ग से ₹58.13 करोड़ की ठगी**
16 अक्टूबर 2025: महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक, 72 साल के बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ₹58.13 करोड़ ठगे गए।

2. **दिल्ली: रिटायर्ड बैंकर से ₹22.92 करोड़ ठगे**
अगस्त-सितंबर 2025: 78 साल के नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगा गया। अप्रैल 2026 में 5 बैंकों को ₹1.31 करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

3. **सूरत: ट्रेडिंग एप से ₹23.38 करोड़ की ठगी**
अक्टूबर 2026: फर्जी ट्रेडिंग एप के जरिए एक महिला से ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

4. **मध्य प्रदेश: क्रिप्टो निवेश में ₹21.06 करोड़ की ठगी**
12 जुलाई 2026: ग्वालियर के 70 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय को फर्जी निवेश योजना में फंसाया। रकम 106 ट्रांजैक्शन से 76 बैंक खातों में भेजी गई।

5. **दिल्ली: NRI दंपती से ₹14.85 करोड़ ठगे**
24 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026: ठगों ने TRAI और सरकारी अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपती को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर रकम ऐंठी।

कोर्ट बोला- लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, 4 बड़ी बातें

1. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल घटना के बाद रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं है, ठगी को रोकने के लिए पहले से इंतजाम जरूरी हैं।
2. खाते में असामान्य लेन-देन होने पर बैंक उसे वेरिफाई तक अस्थायी रूप से क्यों नहीं रोक सकते। संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच और उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी जाए।
3. RBI के प्रस्तावित नियमों में उन मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए, जहां वित्तीय संस्थान जरूरी सावधानी बरतने में विफल रहे हों। अदालत ने RBI से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी मांगी।
4. सुप्रीम कोर्ट ने RBI से प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करने और सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करने को कहा।

28 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे बेरहम अपराधियों को सख्त सजा दी जाए

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को 'डिजिटल डकैती' बताया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह सामान्य जबरन वसूली से ज्यादा गंभीर अपराध है और इसमें खासकर बुजुर्गों को वीडियो कॉल के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने की बात कही। यह टिप्पणी गौरव कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिकाकर्ताओं ने 12 राज्यों में दर्ज 35 साइबर अपराध मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की। आरोप है कि उनकी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और आगे भेजने में हुआ। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी जानकारी के बिना खातों का इस्तेमाल हुआ और वे खुद ठगी के शिकार हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की सुविधा के लिए पीड़ितों को दिल्ली नहीं बुलाया जा सकता और अलग-अलग राज्यों में चल रही जांच को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

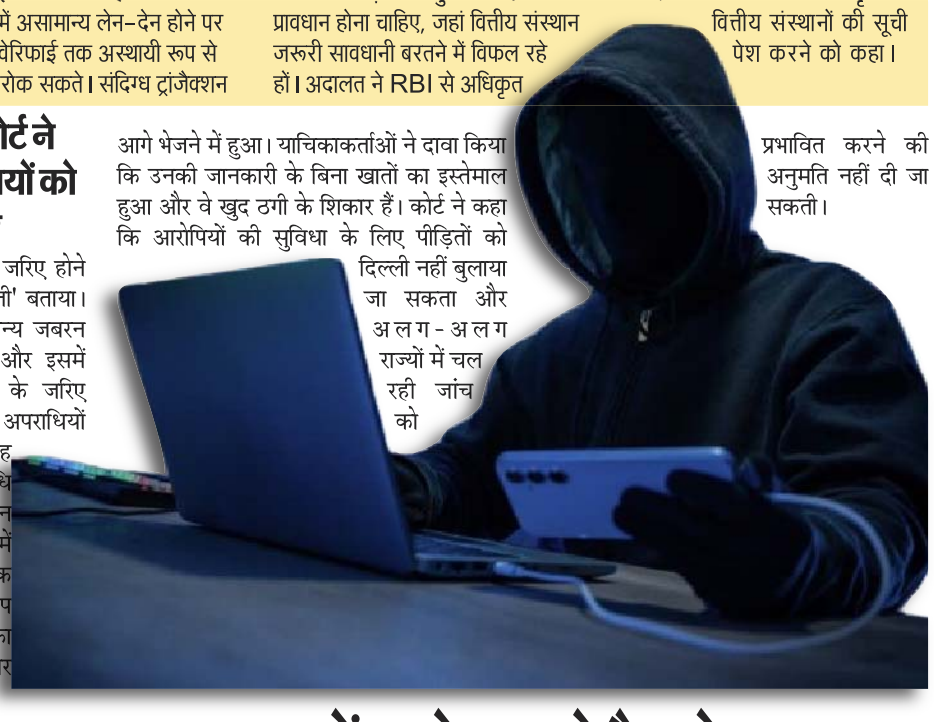

ट्रांसजेंडर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। क्या बायोलॉजिकल तौर पर पुरुष जन्मा व्यक्ति, सर्जरी करवाने के बाद महिला के लिए आरक्षित अधिकारों का दावा कर सकता है... इस सवाल को लेकर एक महिला संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया ने बायोलॉजिक मेल को सर्जरी के बाद सरकारी दस्तावेजों में महिला दर्ज करने की व्यवस्था को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता संगठन 'विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया' ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7और नियम 7 को चुनौती दी है। याचिका के मुताबिक, यह प्रावधान बायोलॉजिकल पुरुषों को सर्जरी के बाद सरकारी दस्तावेजों में खुद को 'महिला' के तौर पर दर्ज कराने की अनुमति देता है।

आईआरसीटीसी ने 1 रुपया कम रिफंड दिया

केरलम कंज्यूमर कोर्ट का आदेश- 9% ब्याज भी देना होगा

₹3100 लौटाएगी अब

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर 1 रुपया कम रिफंड करना IRCTC को महंगा पड़ गया। कासरगोड जिला उपभोक्ता आयोग ने IRCTC को आदेश दिया है कि वह यात्री को 1 रुपए लौटाए, साथ ही 3100 रुपए हर्जाना और मुकदमे का खर्च भी दे।

आयोग ने 1 रुपए पर 9% ब्याज भी लगाया है। सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 100 रुपए मुआवजा देने को कहा। इसके अलावा, मुकदमे का खर्च 3000 रुपए देने का आदेश दिया।

शिकायतकर्ता ने 11 अगस्त 2024 को 553 रुपए में एसी थ्री-टियर ट्रेन टिकट बुक किया था। इस टिकट पर यात्रा 20 अगस्त 2024 को होनी थी। शिकायतकर्ता ने 17 अगस्त को टिकट कैंसिल कर दिया। यह यात्रा की तय तारीख से 48 घंटे से ज्यादा पहले किया गया था। IRCTC ने कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 180 रुपए काटे। इसके अलावा, 5% GST के 9 रुपए भी काटे गए। IRCTC को 30 दिन में भुगतान करना होगा।

पटाखों पर पूरे बैन के पक्ष में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

लेकिन आदेश लागू नहीं हुए तो हर साल निर्देश देना मजाक बन जाएगा

रोक

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों से आदेशों को जमीन पर लागू करने को कहा। दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से प्रदूषण रोकने के उपाय बताए।

>> (शेष पेज 06 पर)

सुप्रीम कोर्ट के 3 कमेंट...

1. **पटाखों पर नियंत्रण जरूरी:** अधिकारियों को पटाखों के इस्तेमाल को सही तरीके से नियंत्रित करना होगा, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
2. **आदेशों पर अमल हो:** हर साल आदेश देने का फायदा नहीं, जब तक अधिकारी मौके पर जाकर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करते।
3. **जन-जागरूकता बढ़ाएं:** खेल जगत की हस्तियों और अन्य लोगों की मदद से पटाखों के नुकसान को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए।

फास्ट न्यूज

नागपुर में जीत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार

मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर MLC चुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। पार्टी ने दावा किया कि फडणवीस ने चुनाव के पूरे नतीजे आने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया।

केरलम मर्सिडीज केस, जज की गिरफ्तारी पर रोक

कोच्चि। केरलम हाईकोर्ट ने कोच्चि के मर्सिडीज हादसे में 17 साल के नाबालिग आरोपी के पिता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जज न्यायिक अधिकारी हैं और जांच में सहयोग कर चुके हैं। वे पूछताछ के लिए भी पेश हुए थे। यह हादसा 24 अक्टूबर की देर रात कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में हुआ था। आरोप है कि जज का नाबालिग बेटा तेज रफ्तार मर्सिडीज चला रहा था।

यूपी में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिंसा पर नौकरी नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बदलने के लिए युवा अगर सड़क पर उतरकर हिंसा करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों, परिषदों, निगमों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती से चुने जाने वाले कैंडिडेट्स के चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया है।

कांग्रेस आज सड़क पर संसद लगाएगी

जनता के बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाएगी

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। INDIA ब्लॉक शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मॉक संसद आयोजित करेगा। इसमें राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'महाभियोग' चलाएंगे। इस कार्यक्रम में राहुल, प्रियंका समेत कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली से पहले किया जा रहा है।

>> (शेष पेज 06 पर)

वहीं, राहुल गांधी ने गुरुवार को छात्र संगठनों से भी 1 नवंबर के दिल्ली चलो मार्च में आने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस-लाठीचार्ज की चिंता नहीं करें।

केंद्र बोला- बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा, 4 दिन पहले ही सरकार ने मंजूरी दी

100% एथेनॉल ईंधन की सप्लाई कैसे होगी : एससी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 100% एथेनॉल वाले ईंधन की सप्लाई कैसे होगी। कोर्ट एथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2025-26 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बेंच ने हाल की मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह सवाल पूछा। 26 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे E100 यानी लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को मंजूरी मिली। 27 अक्टूबर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि पेट्रोल में एथेनॉल 20% से ज्यादा बढ़ाने की केंद्र की कोई तत्काल योजना नहीं है।

>> (शेष पेज 06 पर)

ई85 और ई100 ईंधन पर चलती हैं फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को E85 और E100 जैसे ज्यादा एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चलने के लिए बनाया जाता है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। E100 में करीब 100% एथेनॉल होता है। इसके उलट, सामान्य पेट्रोल गाड़ियों को फिलहाल कम एथेनॉल मिश्रण के लिए मंजूरी मिली है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि बदलावों से उत्सर्जन प्रमाणन के प्रावधान अपडेट होंगे।

एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 का विवाद

30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्देश को ज्यों का त्यों बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसमें ESY 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने को कहा गया था। कोर्ट एक तेल मार्केटिंग कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी का दावा था कि हाईकोर्ट के आदेश से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति अस्थिर हो जाएगी। हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक प्रतिनिधित्व पर विचार कर फैसला लेने का निर्देश दिया था। यह प्रतिनिधित्व एक ऐसे एथेनॉल निर्माता ने दिया था, जिसने ESY 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग की थी।

फैसला : बेटा जेल से छूटेगा, 2 पैन कार्ड मामले में 10 साल की सजा सस्पेंड

आजम खान को जमानत, लेकिन बाहर आना मुश्किल

तमसा संकेत, एजेंसी

गराज/रामपुर। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। दोनों को जमानत भी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम और उनका बेटा अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आजम अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह साफ नहीं है। वजह, आजम के खिलाफ अभी 2 केस पेंडिंग हैं। आजम के खिलाफ एक मामला ईडी ने हाल ही में दर्ज किया है। दूसरा एक मामला 10 सितंबर का है, जिसमें यूपी विजिलेंस ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगर इन मामलों में पुलिस वारंट-बी नहीं लेती है, तो आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, आजम जेल से बाहर आने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें रामपुर में अफसरों को तनखैय्या कहने के मामले में 2 साल की सजा है चुकी है। 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा।

>> (शेष पेज 06 पर)

2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

इस मामले की शुरुआत साल 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर से हुई थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। साल- 2017 में बसपा प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने भी इस बारे में शिकायत की थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले 2 पैन कार्ड थे। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 और दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनाव और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किया गया।

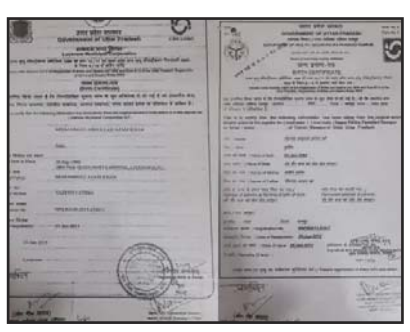

ये वही बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जिनके आधार पर आजम ने बेटे अब्दुल्ला के 2 फर्जी पैन कार्ड बनवाए थे।

सीबीएसई 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य

स्किल पेपर से पास होने का मौका, एआई मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे

मदद

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बताया। इसमें छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा वे एक अतिरिक्त स्किल सब्जेक्ट चुन सकेंगे। इस सब्जेक्ट से मैथ, साइंस या सोशल साइंस में फेल होने पर भी छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद मिल सकती है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे। यह बदलाव उन छात्रों पर लागू होगा, जो 2026-27 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। इससे मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CBSE की डायरेक्टर (एकेडमिक्स) प्रज्ञा एम. सिंह ने बताया कि 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए छात्र कौशल विकास सब्जेक्ट या बोर्ड के 22 स्किल सब्जेक्ट्स में से कोई एक चुन सकेंगे। इसके लिए छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे।

>> (शेष पेज 06 पर)

शिक्षक और कर्मचारियों को आना होगा, पीईटी परीक्षा के चलते फैसला

यूपी के 60 जिलों में आज 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद

तमसा संकेत, एजेंसी

उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में PET-2026 परीक्षा के चलते कल, 30 अक्टूबर को 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत ने इसकी पुष्टि की है। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को 60 जिलों में PET परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए करीब 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शासन की ओर से संबंधित जिलों के DIOS (जिला विद्यालय निरीक्षक) और BSA (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) को

स्कूलों में छुट्टी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी। लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ समेत कई जिलों के DIOS ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। लखनऊ के DIOS के मुताबिक, PET-2026 परीक्षा तीन दिन 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को हो रही है। 25 अक्टूबर को दो पालियों में परीक्षा कराई जा चुकी है। अब 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो-दो पालियों में परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली में करीब 20 से 25 हजार अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावकों के भी आने की संभावना है। ऐसे में शहर में भीड़ बढ़ने की आशंका है।

25 अक्टूबर को परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के जूते-मोजे तक उतरवा लिए गए थे।

केंद्रों पर सख्ती देखने को मिली

परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जांच की गई। बायोमेट्रिक और चेहरे की स्कैनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान कई केंद्रों पर सख्ती देखने को मिली।

लखनऊ में लड़कियों के कलावे काटे गए। उनकी बालियां और हेयर पिन उतरवाई गईं। लड़कों के जूते-मोजे भी उतरवाए गए। कानपुर और बरेली में लड़कियों के बाल खुलवाकर जांच की गई।

अलीगढ़ में महिलाओं ने पायल और गले की चेन उतारकर परिजनों को दी। मथुरा में कुछ लड़कों ने दांत से कलावा काटा। उनकी बेल्ट भी उतरवाई गई। अलीगढ़ में अभ्यर्थियों के रूमाल भी बाहर रखवा लिए गए।

कन्नौज में एक छात्रा गलत परीक्षा केंद्र पहुंच गई। वह रोने लगी तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी उसे बाइक से सही केंद्र तक लेकर पहुंचा। वहीं, गाजियाबाद में दूसरी पाली में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया।

सुरेश यादव ने 2027 में सपा की जीत का दावा

कहा- पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के तीन बार के विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता उसके कामकाज से ऊब चुकी है। यादव ने कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश के एक मंत्री युवाओं को पकौड़ा तलने और एक उपमुख्यमंत्री टेम्पो चलाने की सलाह देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाओं से आम

लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा और देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। यादव ने कहा कि लोग धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम और भोले बाबा का आशीर्वाद सपा को मिला है। एमएलसी चुनाव को लेकर यादव ने मतदाता सूची से लेकर मतगणना तक गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सूची में नाम, पिता के नाम, मोहल्ले और मतदान केंद्र से जुड़ी गलतियां थीं। उनके मुताबिक, अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, जबकि अखिलेश यादव लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं और समर्थक मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने फिर कहा कि 2027 में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आरोपों पर भाजपा और कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

फास्ट न्यूज

रायबरेली में खड़े ट्रक से टकराई बुलेट, युवक की मौत

रायबरेली। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में सिधौना गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से बुलेट बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अर्चित यादव के रूप में हुई है। वह मिल एरिया थाना क्षेत्र के छड़ी का पुरवा के रहने वाले देवेंद्र यादव के बेटे थे। हादसे में बुलेट बाइक क्षतिग्रस्त हो गई।

बारिश से कटी धान की फसल भीगी

रायबरेली। रायबरेली में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हुई बेमौसम बारिश से खेतों में कटी और खुले में रखी धान की फसल भीग गई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के कारण धान के दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने और उपज के उचित दाम मिलने पर असर पड़ने की आशंका है। फिलहाल कितने किसानों की फसल प्रभावित हुई है और कुल कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन संबंधित विभागों के सर्वे के बाद ही हो सकेगा। धान की कटाई के बाद फसल को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी होता है।

बेटे पर पिता को पीटने और धमकाने का आरोप

रायबरेली। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के भनवामऊ गांव में लल्लू पटेल ने अपने बड़े बेटे पर शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जगतपुर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। लल्लू पटेल के मुताबिक, उनके दो बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं। आरोप है कि बड़ा बेटा शराब पीकर घर आता है और उनसे गाली-गलौज करता है।

डबल मर्डर में ब्लॉक प्रमुख समेत 9 को उम्रकैद

आजमगढ़ कोर्ट ने 74-74 हजार जुर्माना लगाया, प्रधानी चुनाव की रंजिश में हत्या की थी

तमसा संकेत, एजेंसी

आजमगढ़। आजमगढ़ की जिला अदालत ने करीब 19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में रानी की सराय के ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 74-74 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला जज कमलापति ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने कहा कि वह अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। यह मामला प्रधानी के चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश से जुड़ा है। करीब 19 साल पहले हुए विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान कुछ अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट भी की गई थी। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले के अनुसार, प्रधानी के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी विवाद के दौरान रामजन्म सिंह, उनके भतीजे अंकित सिंह और आशीष के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घटना के दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें तालुकदार सिंह और पारसनाथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोगों की हत्या के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने घटनाक्रम की जांच की और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की। जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी राधेश्याम सिंह की मौत हो गई। इसके बाद शेष आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रही। अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपने मामले को साबित करने के लिए 17 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने और मामले से जुड़े साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला जज कमलापति ने नौ आरोपियों को हत्या का दोषी माना। अदालत ने सभी नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले के साथ करीब 19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में सुनवाई के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया। अदालत का फैसला आने के बाद रानी की सराय के ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं।

2007 में हुई थी दो लोगों की हत्या

सरकारी वकील ने बताया- 21 अक्टूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब 9 बजे रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव निवासी रामजन्म सिंह अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी ग्राम प्रधान विपिन सिंह समेत 10 लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे। आरोप है कि विपिन सिंह के ललकारने पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान विपिन सिंह ने तालुकदार सिंह को गोली मार दी, जबकि राजेश सिंह ने पारसनाथ सिंह को गोली मार दी।

जिला अधिकारी ने सड़कें ठीक करने के निर्देश दिए

हापुड़ में जल जीवन मिशन की समीक्षा

तमसा संकेत, एजेंसी

हापुड़। हापुड़ में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पेयजल योजनाओं, पाइपलाइन बिछाने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत और गांवों में पेयजल सप्लाई की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 200 पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से 76 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2026 तक 100 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है। जिला अधिकारी कविता मीना ने बाकी काम तेजी से पूरा कर मार्च 2027 तक सभी योजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने पाइपलाइन बिछाने के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने को

कहा। उन्होंने संबंधित गांवों में 15 नवंबर 2026 तक सड़कें ठीक करने के निर्देश दिए। अधिकारियों और काम करने वाली फर्म से नियमित निगरानी कर बाकी काम समय पर पूरा कराने को कहा। सड़क मरम्मत से जुड़ी समस्या या शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों से 'जल सारथी ऐप' डाउनलोड करने की अपील की गई। ऐप पर मिली शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी कविता मीना ने कहा कि जिन गांवों में नियमित पेयजल सप्लाई हो रही है।

एटा में करवा-चौथ के दिन हादसे में युवक की मौत

दोनों बाइकों में भिड़ंत, पत्नी के लिए सामान खरीदने निकला था

तमसा संकेत, एजेंसी

जैथरा(एटा), एटा। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर वरना रोड पर ढाकपुरा स्थित राजकीय महाविद्यालय के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 33 वर्षीय अंशुल पांडेय की मौत हो गई। अंशुल, विजेंद्र सिंह पांडेय के बेटे थे और वरना गांव के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक, वह घर से जैथरा बाजार जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जैथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के चाचा गुड्डू पांडे द्वारा बताया गया कि अंशुल बालाजी

इंटरप्राइजेज के नाम से इंटरलॉकिंग के व्यवसाई थे। अंशुल की शादी करीब छह साल पहले हुई थी। उनका पांच साल का बेटा अभिनय है। वह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे।

उनके पिता विजेंद्र सिंह वरना उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर के पद पर तैनात हैं पत्नी आरती गृहणी है। अंशुल की पत्नी आरती करवा चौथ की तैयारी कर रही थीं और उनके घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। हादसे की खबर के बाद गांव में शोक का माहौल है।

बाराबंकी में सांप को पॉलिथीन में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर

धान का पुआल भरते समय युवक को सांप ने काटा

तमसा संकेत, एजेंसी

फतेहपुर। थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में गुरुवार को खेत में धान का पुआल ट्राली में भर रहे 22 वर्षीय अश्वनी कुमार को सांप ने काट लिया। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फतेहपुर लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) की 20 खुराक दीं, लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी वाहन से लखनऊ ले गए। अवधेश कुमार के बेटे अश्वनी गुरुवार को खेत में पुआल भर रहे थे। इसी दौरान पुआल के नीचे छिपे सांप ने उनके दाहिने पैर में काट लिया। परिजन

करीब 20 मिनट के भीतर उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात डॉ. हिमांशु ने जांच के बाद उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के मुताबिक, उपचार के बावजूद हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। डायलिसिस की संभावना को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया।

सांप लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, मची अफरातफरी

परिजनों के मुताबिक, अश्वनी के पिता अवधेश वर्मा ने खेत में पुआल के नीचे से सांप निकालकर मार दिया था। इसके बाद उसे पॉलिथीन में रखकर अस्पताल ले आए, ताकि चिकित्सक उसकी पहचान कर सकें। सांप को चिकित्सक की मेज पर रखे जाने से वहां मौजूद मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्यकर्मियों में घबराहट फैल गई। कुछ देर के लिए अस्पताल में अफरातफरी का माहौल बन गया।परिजनों ने सांप की पहचान फुरसा प्रजाति के जहरीले सांप के रूप में बताई। हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अश्वनी को लखनऊ के किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी वर्तमान हालत कैसी है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।

> **सीएचसी अधीक्षक डॉ. अवनीश चौधरी ने बताया कि अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अश्वनी को सरकारी अस्पताल में उपचार दिया गया और परिजनों के मुताबिक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया। परिजनों ने बताया कि खेत में पहले भी सांप निकल चुके हैं, लेकिन इससे पहले कोई हादसा नहीं हुआ था। अश्वनी को लखनऊ के किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी वर्तमान हालत कैसी है।**

जीत : राजीव शिक्षक राजनीति का नया चेहरा, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री पसंद नहीं आई

ध्रुव त्रिपाठी चौथी बार एमएलसी बने

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में ध्रुव कुमार त्रिपाठी लगातार चौथी बार विधान परिषद पहुंचने में सफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। दूसरे स्थान पर रहे राजीव यादव ने शिक्षकों के बीच मजबूत समर्थन हासिल कर सबका ध्यान खींचा।

चुनाव में राजनीतिक दलों की एंट्री और शिक्षक संगठनों की भूमिका अहम मुद्दे रहे। राजीव यादव ने राजनीतिक दलों के दखल के विरोध को अपना चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका उन्हें फायदा मिलता दिखाई दिया। वहीं, डॉ. संजयन त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जीत की उम्मीदों को झटका लगा। डॉ. संजयन त्रिपाठी पहले भाजपा और फिर सपा से जुड़े। उन्हें

उम्मीद थी कि स्कूलों के अपने संपर्कों के साथ सपा के आधार मतदाताओं का समर्थन जोड़कर वह मुकाबले में मजबूत स्थिति बना लेंगे। लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और वह तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव में उनके प्रदर्शन से यह संकेत मिला कि केवल राजनीतिक दल का समर्थन या अपने मतदाताओं पर भरोसा जीत के लिए पर्याप्त नहीं रहा। शिक्षकों के बीच संगठन, मुद्दों और उम्मीदवार की स्वीकार्यता ने भी अहम भूमिका निभाई।

भाजपा का टिकट मिलने के बाद ध्रुव के सामने बदली चुनौती

ध्रुव कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। उन्होंने संगठन के जिलाध्यक्ष से लेकर विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने तक का सफर तय किया है। सदन में शिक्षकों की समस्याएं उठाने और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए उनकी पहचान रही है।

संगठन की मजबूती और अपनी सक्रियता के दम पर उन्हें लगातार चौथी जीत का भरोसा था।

लेकिन भाजपा से टिकट मिलने के बाद शिक्षक संगठनों के भीतर राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ शिक्षकों की नाराजगी की बात भी सामने आई।

मतगणना के दौरान उन्हें हर राउंड में चुनौती का सामना करना पड़ा और जीत का अंतर अपेक्षा से कम रहा।

राजीव यादव ने पुरानी पेंशन और राजनीतिक दखल को बनाया मुद्दा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव लगातार पुरानी पेंशन और शिक्षकों की सेवा संबंधी मांगों को लेकर सक्रिय रहे हैं। इस चुनाव में उन्होंने शिक्षक राजनीति में राजनीतिक दलों की एंट्री पर सवाल उठाए और इसे प्रमुख मुद्दा बनाया। उनके समर्थन में एडेड स्कूलों के शिक्षकों की भूमिका खास रही। दावा है कि इन स्कूलों में उन्हें करीब 70 प्रतिशत तक समर्थन मिला। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद राजीव ने शिक्षक राजनीति में अपनी पहचान मजबूत की है। उनके प्रदर्शन से संगठन की स्थिति भी मजबूत हुई है।

अखिलेश को लेडी इन्फ्लुएंसर ने बताया उत्तराखंड का जमाई

बोलीं- ससुराल वालों से माफी मांग लो, हमारी बेटी से कुछ गड़बड़ हो गई क्या

तमसा संकेत, एजेंसी

देहरादून। हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी ने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया बताने वाले अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अखिलेश यादव को उत्तराखंड का 'जवाई' (दामाद) बताते हुए कहा कि वे अपने जवाई को समझाकर ससुराल वालों से माफी मंगवा लेंगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अखिलेश यादव को थोड़ा छल लग गया है, वे एक-दो दिन में ठीक हो जाएंगे। हालांकि, जब तक वे अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा। दरअसल, पांच दिन पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा

घुसपैठिए उत्तराखंड के हैं। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड में विरोध हो रहा है। ज्योति अधिकारी ने कुमाऊंनी और हिंदी में वीडियो जारी कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ज्योति अधिकारी ने यूपी में अपने रिश्तेदारों के नामकरण के इनविटेशन पर यह बात कही है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव की पत्नी खुद उत्तराखंड से हैं। उनका परिवार पहले पौड़ी में रहता था, लेकिन बाद में देहरादून के जोगीवाला शिफ्ट हो गया था।ज्योति अधिकारी ने कुमाऊंनी अंदाज में कहा, ₹यह जो अखिलेश जी हैं, ये हमारे जवाई हैं। हमारी चेली (बेटी) से कुछ गड़बड़ हो गई है। अब जवाई को हम अपने पास बुलाकर अच्छी तरह समझा देंगे।₹ उन्होंने हंसते हुए अखिलेश यादव से उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगने को भी कहा। वीडियो में उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी मजाकिया अंदाज में बातचीत करते नजर आए। ज्योति अधिकारी ने उत्तराखंड के विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर सड़कों पर उतरने और पुतले फूंकने वाले नेताओं की भावनाएं आज आहत क्यों नहीं हो रही हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाता है, जिनसे उसे राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद होती है।

सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर विपक्ष से मांगा जवाब, बोले- 2027 में भी सपा को हार का सामना करना पड़ेगा

एमएलसी चुनाव के नतीजों से विधानसभा का आकलन बेमानी: ओमप्रकाश राजभर

विरोध

बृजेंद्र वीर सिंह

अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में मतदाताओं की संख्या विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम होती है, इसलिए दोनों चुनावों के परिणामों की तुलना करना उचित नहीं है। राजभर ने विपक्ष के ईवीएम और वोट चोरी संबंधी आरोपों पर सवाल उठाए। साथ ही सपा के पीडीए नारे पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में

भी सपा को हार का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजभर ने विपक्ष पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो नेता ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों पर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। राजभर ने विपक्ष के चुनावी आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को अपने दावों के समर्थन में भी स्पष्टता रखनी चाहिए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भाजपा के चुनावों में कमजोर होने और धांधली के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि यदि विपक्ष को चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत है, तो उसके 37 सांसदों और 111 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। राजभर का कहना था कि चुनावी नतीजों पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को अपने आरोपों को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए।

2017 और 2022 के चुनावों का हवाला, 2027 पर भी किया दावा

राजभर ने कहा कि सपा को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था और 2027 में भी पार्टी हारेगी। उन्होंने एमएलसी चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से जोड़ने पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के चुनावी दावों को खारिज किया। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। हालांकि, वर्ष 2027 के चुनाव के परिणाम अभी भविष्य की बात हैं और राजभर का बयान उनके राजनीतिक दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।

एमएलसी और विधानसभा चुनाव के मतदाताओं में अंतर बताया

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि एमएलसी चुनाव में करीब 14 लाख मतदाता थे, जिनमें से लगभग छह लाख लोगों ने मतदान किया। इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक मतदाता होते हैं और आठ करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शौचालय, पेंशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले बड़ी संख्या में आम मतदाता एमएलसी चुनाव में मतदान के पात्र नहीं थे। ऐसे में एमएलसी चुनाव के परिणामों को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करना उचित नहीं है।

सपा के पीडीए नारे पर साधा निशाना

सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे पर भी राजभर ने टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जातिवाद की राजनीति करती है। गोरखपुर एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने संजय त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को लेकर भी सपा पर आरोप लगाए। राजभर के बयान में पीडीए की राजनीति और एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर सपा की रणनीति पर सवाल उठाए गए। ये आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शौचालय, पेंशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले बड़ी संख्या में आम मतदाता एमएलसी चुनाव में मतदान के पात्र नहीं थे। ऐसे में एमएलसी चुनाव के परिणामों को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करना उचित नहीं है।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव

घर से कुछ दूरी पर वायर के सहारे लटका था शव

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के नगपुर मुस्तफाबाद गांव में गुरुवार सुबह 28 वर्षीय रवि मौर्य का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घर से कुछ दूरी पर पेड़ से वायर के सहारे शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक की मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत की वास्तविक वजह सामने लाने की मांग की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और दो मोबाइल फोन कब्जे में लेने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नगपुर मुस्तफाबाद निवासी रवि मौर्य पुत्र पारस मौर्य का शव गुरुवार सुबह घर के करीब एक पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक की मौत को लेकर सवाल उठाए और मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए। हालांकि, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। रवि दो भाइयों में बड़ा था।

फास्ट न्यूज

एसपी ने सुनीं फरियादियों की शिकायतें

अंबेडकरनगर। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें पुलिस अधीक्षक के सामने रखीं।

सऊदी अरब से गांव पहुंचा कमलेश का पार्थिव शरीर

गोरखपुर। सऊदी अरब के दम्मम में काम करने वाले बांसगांव निवासी कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर मंगलवार, 27 अक्टूबर को उनके पैतृक गांव पहुंचा। शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बाद में स्थानीय श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कमलेश का 21 अक्टूबर को सऊदी अरब में निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद से परिवार उनके पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार कर रहा था।

टीनशेड में अटका छात्रावास निर्माण

अंबेडकरनगर। जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं के लिए प्रस्तावित नए छात्रावास का निर्माण परिसर में लगे टीनशेड के कारण बाधित हो रहा है। 24 छात्राओं की क्षमता वाले इस छात्रावास के लिए निर्धारित जगह खाली नहीं हो पा रही है। साथ ही जिलाधिकारी समेत अन्य उच्चाधिकारियों से शिकायत कर संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय में छात्राओं की आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिए नया छात्रावास बनाया जाना है।

पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर उठे सवाल

अकबरपुर के लोरपुर ताजन का मामला

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लोरपुर ताजन में पत्रकार मोहम्मद इसराइल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। इसराइल ने पुलिस पर प्रारंभिक जांच के बिना मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर समाप्त करने की मांग की है। प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेंद्र वीर सिंह ने प्रकरण में न्याय की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। मोहम्मद इसराइल के मुताबिक, 23 और 24 तारीख की रात उनके पिता, पत्नी और छोटे बच्चों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद शफीक, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद कुद्दूस और मोहम्मद सिद्दीक के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसराइल का आरोप है कि घटना के तीन दिन बाद दूसरे पक्ष के मोहम्मद तौफीक ने ब्लेड से काटने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। उनका कहना है कि सूचना मिलने पर वह अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इसराइल के अनुसार, मामले की जांच उपनिरीक्षक इशहाक खान को सौंपी गई थी। उन्होंने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बयान लिए और वीडियो भी बनाया।

उद्योग बंधु की बैठक में डीएम ने लाभार्थी को सौंपा डेमो चेक, सीएम युवा समेत कई योजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा

बालूशाही उद्योग को 50 लाख का ऋण, टांडा में खुलेगी नई शाखा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिले के पारंपरिक व्यंजन बालूशाही के कारोबार को बढ़ावा देने और उद्यम के विस्तार के लिए गैली फूड्स को 50 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की अकबरपुर शाखा से यह ऋण स्वीकृत किया गया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की बैठक के दौरान गैली फूड्स के संचालक रिंकू उपाध्याय को डेमो चेक प्रदान किया। बैठक में कारोबार के विस्तार के लिए टांडा में नई शाखा खोलने का प्रस्ताव भी सामने आया। जिले की पहचान बालूशाही जैसे पारंपरिक व्यंजन से जुड़ी है।

इसके कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। गैली फूड्स को मिले 50 लाख रुपये के ऋण से कारोबार के विस्तार में मदद मिलने की उम्मीद है। टांडा में नई शाखा खोलने का प्रस्ताव भी इसी विस्तार की दिशा में एक कदम है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की बैठक में जिले के औद्योगिक विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), एक जनपद एक व्यंजन योजना और निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों से योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की जानकारी ली गई। साथ ही उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक स्तर पर लंबित ऋण आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि युवाओं और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के साथ निवेश से जुड़े आवेदनों के निस्तारण में भी विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा जाए। बैठक का उद्देश्य जिले में उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना रहा।

टांडा में कारोबार बढ़ाने की तैयारी

बैठक में गैली फूड्स के संचालक रिंकू उपाध्याय की ओर से टांडा में नई शाखा खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई। इससे खाद्य कारोबार के विस्तार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं। नई शाखा खुलने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना, निवेश को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक गतिविधियों को गति देना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों और बैंक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

दीपावली से पहले ढाई क्विंटल से अधिक मिठाई पकड़ी, डिब्बों में मिली फफूंद

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अकबरपुर बस स्टेशन के पास पकड़ा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। दीपावली से पहले जिले में मिठाई की खेप पकड़े जाने से खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में बस स्टेशन के पास खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई से भरी एक वैन पकड़ी। वैन में ढाई क्विंटल से अधिक मिठाई लदी थी। जांच के दौरान डिब्बों में रखी मिठाई पर फफूंद लगी मिली।

टीम ने मिठाइयों के नमूने लिए हैं। जानकारी के अनुसार, मिठाई बस्ती जिले से अंबेडकरनगर लाई जा रही थी। दीपावली के मद्देनजर मिठाइयों की मांग बढ़ने के बीच इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से उनकी गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की जांच की और नमूने एकत्र किए।

जिले में बड़े पैमाने पर नकली मिठाई खपाए जाने की आशंका जताई जा रही है।

शहर के कई मिष्ठान भंडारों तक ऐसी मिठाइयों की सप्लाई होने की चर्चा भी है। हालांकि, किन दुकानों पर मिठाई भेजी जानी थी और पकड़ी गई खेप में कितनी मिठाई मानकों के अनुरूप नहीं थी, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। दीपावली पर मिठाइयों की खरीदारी बढ़ने के कारण उनकी गुणवत्ता की जांच अहम हो गई है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और नमूनों की जांच से मिठाई की गुणवत्ता के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।

टांडा में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का स्वागत, संगठन को मजबूत करने पर जोर

मिशन योगी अगेन सीएम की प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रभावती यादव ने टोली के साथ दीपिका शाह का किया अभिनंदन

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। टांडा में मिशन योगी अगेन सीएम उत्तर प्रदेश संगठन के महिला मोर्चा की ओर से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दीपिका शाह का स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रभावती यादव ने किया।

इस दौरान संगठन की पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ताओं ने दीपिका शाह का सम्मान कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। टांडा में आयोजित स्वागत समारोह में प्रभावती यादव अपनी टोली के साथ शामिल हुईं। उनके नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा

महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दीपिका शाह का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आपसी मेलजोल के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

महिला कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। स्वागत समारोह के दौरान संगठन को मजबूत बनाने और उसकी गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठनात्मक कार्यों को गति देने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग जरूरी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और मिलकर काम करने की बात भी सामने आई। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही संगठन के विस्तार के लिए आपसी सहयोग बनाए रखने की बात कही गई।

स्वागत समारोह के दौरान महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी सक्रियता प्रदर्शित की।

कार्यक्रम में संगठन को आगे बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने पर चर्चा हुई। इस आयोजन के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया।

हादसा : नवानगर के पास ई-रिक्शा ने बाइक में मारी टक्कर, पहिए के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हुईं कादंबरी मिश्रा

करवा चौथ से एक दिन पहले हादसे में गई शिक्षिका की जान

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 55 वर्षीय शिक्षिका कादंबरी मिश्रा की मौत हो गई। बुधवार को वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने अधिवक्ता पति सत्य प्रकाश मिश्र के साथ बाइक से घर लौट रही थीं। नवानगर के पास अकबरपुर की ओर से आ रहे ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और कादंबरी सड़क के दाहिनी ओर जा गिरीं। इसी दौरान ई-रिक्शा उनके ऊपर से गुजर गया। गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को

परिजन अकबरपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया।स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसाकादंबरी मिश्रा मालीपुर थाना क्षेत्र के कांदीपुर गांव की निवासी थीं। वह जलालपुर स्थित अमर गांधी बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। उनके पति सत्य प्रकाश मिश्र जलालपुर तहसील में अधिवक्ता हैं। बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बाइक से अपने घर के लिए निकले थे।बताया गया कि जब वे अकबरपुर-जलालपुर मार्ग पर नवानगर के पास पहुंचे, तभी अकबरपुर की तरफ से आ रहे ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।सड़क पर गिरते ही ई-रिक्शा के नीचे आईबाइक गिरने के बाद कादंबरी मिश्रा सड़क की दाहिनी ओर जा गिरीं। इसी दौरान ई-रिक्शा उनके ऊपर से निकल गया।

हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पति सत्य प्रकाश मिश्र ने तत्काल परिवार के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कियागंभीर रूप से घायल कादंबरी मिश्रा को परिजन जल्दबाजी में अकबरपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

पति के साथ घर लौट रही थीं कादंबरी

कादंबरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले हुए हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। जहां पर्व की तैयारी होनी थी, वहां अचानक अपनों को खोने का दुख छा गया। हादसे में पत्नी को खोने वाले सत्य प्रकाश मिश्र के लिए यह घटना बड़ा आघात बन गई। कादंबरी मिश्रा दो बेटियों की मां थीं। बड़ी बेटी आकांक्षा (23) लखनऊ में बीटेक की पढ़ाई कर रही है, जबकि छोटी बेटी प्रतीक्षा (21) लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। मां की मौत की सूचना मिलते ही दोनों बेटियां घर पहुंचीं। परिवार में मातम छा गया और दोनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे के बाद परिजनों ने कादंबरी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव का महादेवा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कादंबरी की मौत से परिवार में शोक है।

शिकायतों की गलत आख्या पर गिरी गाज, लेखपाल रामयश निलंबित

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में गलत रिपोर्टिंग करना भीटी तहसील के लेखपाल रामयश को भारी पड़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी (एसडीएम) तृप्ति गुप्ता ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों पर गलत आख्या प्रस्तुत करने वाले अन्य लेखपालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे मौके पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शिकायत की वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना या तथ्यों से अलग आख्या लगाने पर निस्तारण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

भीटी तहसील में आईजीआरएस रिपोर्टिंग में अनियमितता पर एसडीएम तृप्ति गुप्ता की कार्रवाई, गलत रिपोर्ट लगाने वालों को भी चेतावनी

इसी तरह की रिपोर्टिंग में अनियमितता सामने आने के बाद भीटी तहसील के लेखपाल रामयश के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया।

एसडीएम तृप्ति गुप्ता ने कहा कि भीटी तहसील में किसी भी लेखपाल की ओर से शिकायत पर गलत आख्या लगाए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का जोर है कि आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण तथ्यों के आधार पर किया जाए। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को मौके की स्थिति की सही जानकारी जुटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई से शिकायतों की रिपोर्टिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और तथ्यों की शुद्धता बनाए रखना जरूरी है।

सम्पादकीय

टाटा पर राहुल का बड़ा बयान

देश के सबसे पुराने और अग्रणी औद्योगिक घरानों में एक टाटा समूह में चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। जो अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कारोबारी नेता में इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा है, 'आप कब तक चुप रहेंगे? क्या तब तक जब तक वे आप पर पूरी तरह कब्जा न कर लें? भारतीय उद्योग मोदी और शाह का खिलौना नहीं हैं। आप में हिम्मत नहीं है। हममें है। हम इन अपराधों के लिए न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी के इस पोस्ट के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी पोस्ट आया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी मेरी सलाह है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आप हर मुद्दे का राजनीति-करण करने से बचें। साथ ही, व्यावसायिक और कानूनी मामलों को बिना सोचे-समझे 'आपराधिक' करार देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आपने बार-बार भारतीय उद्योग जगत और हमारे उद्यमियों की सफलताओं की आलोचना की है। क्या अब आप हमारे व्यापारिक नेताओं को भी अपने साथ मिलाकर अविश्वास और नफरत फैलाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? दशकों तक, आपकी पार्टी ने 'लाइसेंस-कोटा राज'' के जरिए भारतीय उद्यमियों की भावना को दबाए रखा और करोड़ों भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भारतीय उद्योग जगत को 'रोजगार पैदा करने वाले' और 'आर्थिक विकास को गति देने वाले के रूप में महत्व देती है। राजनीतिक दलों, नेताओं, सरकारों और संस्थानों की यह समान जिम्मेदारी है कि वे हमारे उद्योगों का समर्थन करें, किसानों को मजबूत बनाएं और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करें। इसलिए, अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय, रचनात्मक तरीके से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को न्याय की गारंटी देता है और हमारे माननीय न्यायालय इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए राहुल जी, हर जगह भूत-प्रेत देखने से बचें। जिस तरह का चिढ़ भरा जवाब वित्त मंत्री ने दिया है, वह प्याज के महंगे होने पर मैं प्याज नहीं खाती, वाले स्तर का ही है। राहुल की चिंता का मूल यही है कि मोदी सरकार में केवल दो उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। व्यापार-कारोबार में एकाधिकार की प्रवृत्ति देश के लिए घातक होती है, यह बात राहुल गांधी कई सालों से लगातार उठा रहे हैं। लेकिन उनकी चिंता का तार्किक समाधान प्रस्तुत करने की जगह उन्हें व्यापार विरोधी साबित किया जाता है। अभी रामलीला मैदान में रैली के पहले जिस तरह एक अनजाने से व्यापारी संगठन से राहुल को चि_ी लिखवाई गई कि व्यापार का नुकसान होगा, इसलिए रैली टाल दो, वह भी यही दिखाने की कोशिश है कि राहुल को कारोबारियों से बैर है। जबकि राहुल गांधी ने हमेशा लघु और मध्यम कारोबारियों के लिए आवाज उठाई। नोटबंदी और जीसएटी लागू होने पर उनकी परेशानियों की बात कही। और अब राहुल को व्यापार में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण टाटा जैसे बड़े औद्योगिक घराने के हक में भी बोलने के लिए सामने आना पड़ा है। बता दें कि टाटा घराने में विवाद टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त करने के फैसले को लेकर है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा परिवार से ही आने वाले नोएल टाटा ने इस फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि बोर्ड की बैठक में जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उन्होंने फैसले को अमान्य बताते हुए कंपनी से सात दिन के भीतर कई दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगे हैं। उनका आरोप है कि बोर्ड की बैठक के लिए निदेशकों को जो एजेंडा भेजा गया था, उसमें चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का साफ़ उल्लेख नहीं था। नोएल टाटा का कहना है कि इसके बावजूद बैठक में यह प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और कंपनी ने बाद में इसे मंजूर प्रस्ताव के रूप में पेश किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बैठक के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड, अंतिम मिनट्स और प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति मांगने के बावजूद उन्हें ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। गौरतलब है कि टाटा समूह की संरचना में टाटा ट्रस्ट्स की अहम भूमिका है।

जियो की छलांग और विकसित भारत की नई आर्थिक गाथा

> अनंत अंबानी ने जियो के नाम में छिपे आशीर्वाद के भाव को जिस आत्मीयता से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय संस्कृति, पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर संगम है।

किसी राष्ट्र की प्रगति केवल ऊँची इमारतों, चमचमाती सड़कों और बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसकी उद्यमशीलता कितने लोगों के जीवन को बदलती है, तकनीक कितनी दूर तक पहुँचती है और आर्थिक शक्ति किस सीमा तक जनसामान्य की आकांक्षाओं को पंख देती है। भारत की विकास यात्रा में रिलायंस समूह और जियो की कहानी इसी व्यापक परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारत के औद्योगिक इतिहास में टाटा समूह ने विश्वास, संस्थागत मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालीन दृष्टि की मजबूत विरासत निर्मित की है। दूसरी ओर, रिलायंस समूह ने बड़े पैमाने पर निवेश, बाजार की नब्ज पहचानने, तकनीक को जनसुलभ बनाने और नए क्षेत्रों में निर्णायक प्रवेश करने की क्षमता से अपनी अलग पहचान बनाई है। दोनों समूह भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसे में रिलायंस का टाटा समूह से आगे निकलना किसी एक की पराजय और दूसरे की विजय भर नहीं है, इसे भारतीय उद्योग जगत में प्रतिस्पर्धा के नए अध्याय के रूप में देखना अधिक उचित होगा। जियो की यात्रा एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश के बाद उसने इंटरनेट सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने, डेटा की कीमतों में व्यापक बदलाव लाने और डिजिटल गतिविधियों को आम नागरिक तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो की असली उपलब्धि केवल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी का दायरा विस्तृत करना है। रिलायंस की सफलता को मुकेश अंबानी के नेतृत्व में विकसित दीर्घकालीन कारोबारी दृष्टि, बड़े निवेश और बदलते समय के अनुरूप व्यवसाय का विस्तार करने की रणनीति के संदर्भ में समझना चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने जिस उद्यमशीलता को व्यापक जनभागी-दारी और पूँजी बाजार से जोड़ने की नींव रखी, उसे आगे बढ़ाते हुए समूह ने पेट्रोके-मिकल, ऊर्जा, खुदरा व्यापार और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की। जियो ने इस विरासत को डिजिटल युग की आवश्यकताओं से जोड़ा। इस यात्रा का संदेश स्पष्ट है-समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है, जो समय की आहट पहचान लेता है, वही भविष्य की दिशा तय करने लगता है। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता ने इस यात्रा को नया आयाम दिया। लगभग 30,213 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के बाद कंपनी का बाजार पूँजीकरण 12.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया और कारोबार के पहले दिन यह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई। रिलायंस समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य भी टाटा समूह से आगे निकल गया। ये आँकड़े भारतीय पूँजी बाजार के बदलते स्वरूप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि बाजार पूँजीकरण कंपनियों के मूल्यांकन का पैमाना है, आम नागरिक की समृद्धि का नहीं। शेयर बाजार में ऊँचाई तभी सार्थक है, जब उसका लाभ अर्थव्यवस्था की जड़ों तक पहुँचे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदत्त अनंत अंबानी का भावपूर्ण वक्तव्य चर्चाओं में हैं, उन्होंने इस व्यावसायिक उपलब्धि को पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक संवेदना से जोड़कर अर्थ के साथ अध्यात्म के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कारोबार की तुलना पूजा से और शेयरों को प्रसाद की तरह देश के साथ साझा करने की भावना से की। उनके शब्दों में कृतज्ञता, पारिवारिक विरासत और लाखों ग्राहकों के योगदान की स्वीकृति थी। मुकेश अंबानी का भावुक होना भी इस बात का प्रतीक था कि किसी बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का परिश्रम, संघर्ष, विश्वास और पीढ़ियों के सपने जुड़े होते हैं। यहाँ एक विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है-व्यापार केवल लाभ कमाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास अर्जित करने का माध्यम भी है। जब कोई कंपनी अपनी सफलता में कर्मचारियों, तकनीशियनों, साझेदारों और उपभोक्ताओं के योगदान को स्वीकार करती है, तब उद्यम का मानवीय पक्ष सामने आता है। फलदार वृक्ष जितना ऊँचा होता है, उसकी शाखाओं में उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए। यही विनम्रता किसी कारोबारी साम्राज्य को स्थायी प्रतिष्ठा प्रदान करती है। अनंत अंबानी की पशुसेवा और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता भी इसी व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में देखी जा सकती है। उद्योग की वास्तविक प्रतिष्ठा तब बढ़ती है, जब आर्थिक प्रगति के साथ जीवों के प्रति करुणा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी आगे बढ़े।

दूरसंचार क्षेत्र की अग्रणी कम्पनी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीएल) के संस्थापक एवं उद्योगपति महेंद्र नाहटा ने जियो के ऐतिहासिक लॉन्चिंग समारोह में सहभागिता करते हुए इसे भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक संवेदना का अनूठा संगम बताया। उनके अनुसार, जियो की यह उड़ान केवल एक कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल सामर्थ्य, उद्यमशीलता और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा का प्रतीक है। उनके अनुसार अनंत अंबानी के आशीर्वाद, संस्कार और जनभागीदारी से जुड़े भावपूर्ण उद्बोधन ने इस आयोजन को मानवीय संवेदनाओं की विशिष्ट ऊँचाई प्रदान की। निस्संदेह, जियो की यह उड़ान नए भारत के आत्मविश्वास, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक अध्याय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान, आधारभूत डिजिटल सुविधाओं और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने वाली पहलों ने देश के तकनीकी परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। इस विकास में सरकार की नीतियों, निजी क्षेत्र के निवेश, वैज्ञानिक प्रतिभा और करोड़ों नागरिकों की भागीदारी का साझा योगदान है। जियो ने इस वातावरण का उपयोग करते हुए डिजिटल संपर्क का विस्तार किया। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी इसी व्यापक विकास यात्रा का हिस्सा है। परंतु आर्थिक आकार के साथ प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार भी उतना ही आवश्यक है। आगे की चुनौती और भी बड़ी है।

ललित गर्ग

अर्थशास्त्र के बुनियादी ...

अशोक भाटिया

त्योहारी लिक्विडिटी बनाम राजकोषीय असंतुलन

केन्द्र सरकार द्वारा दीवाली और त्योहारों के ठीक मुहाने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभो-गियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देना महज एक प्रशासनिक या नियमित वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह सुस्त पड़ती घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने और व्यापक आर्थिक संतुलन साधने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा नीतिगत कदम है। इस निर्णय के तहत डीए को मूल वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से देश के लगभग 49.18 lakh केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 lakh पेंशनभोगियों की जेब में सीधे तौर पर अतिरिक्त नकदी पहुँचेगी, जो त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और खुदरा बाजार में मांग को एक नया संवेग देने का काम करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में, जहां निजी उपभोग में आंशिक सुस्ती और खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, वहां एक करोड़ से अधिक परिवारों की क्रय शक्ति को सीधे तौर पर बढ़ाना बाजार में तरलता या लिक्विडिटी का प्रवाह तेज करने का एक प्रभावी शॉर्ट-टर्म जरिया साबित हो सकता है। परंतु, अर्थशास्त्र का यह शाश्वत नियम है कि कोई भी वित्तीय प्रोत्साहन मुफ्त में नहीं आता; इस लोक-लुभावन और तात्कालिक राहत देने वाले कदम के पीछे राजकोषीय घाटे का एक भारी-भरकम गणित और राजकोषीय असंतुलन का एक गंभीर अंतर्निहित जोखिम भी छिपा हुआ है जिसे नीति निर्माताओं द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के आर्थिक निहितार्थों को समझने के लिए सबसे पहले बाजार में इसके माध्यम से होने वाले लिक्विडिटी के तात्कालिक प्रभाव का विश्लेषण करना आवश्यक है। दीवाली, धनतेरस और भाईदूज जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर खरीदारी और निवेश की प्रवृत्ति होती है। पिछले कुछ तिमाहियों से यह देखा जा रहा था कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में मध्यम वर्ग बढ़ती रोजमर्रा की महंगाई, विशेषकर खाद्य वस्तुओं के दामों में उछाल के कारण अपने गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा था। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन-भोगियों की आय में इस तीन प्रतिशत की वृद्धि से बाजार में करीब 9,448.35 crore रुपये की अतिरिक्त नकदी सीधे खर्च के रूप में प्रवाहित होने का अनुमान है। जब यह पैसा बाजार में आता है, तो यह केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक आर्थिक गुणक प्रभाव पैदा करता है। कर्मचारी इस अतिरिक्त आय का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, नए वस्त्रों, और त्योहार से जुड़ी सेवाओं पर खर्च करेंगे, जिससे अंततः विनिर्माण क्षेत्र और खुदरा व्यापारियों को भारी राहत मिलेगी। बाजार में वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी, जो एक तरह से सरकार के कर राजस्व को वापस समृद्ध करने में मदद करेगा। इस दृष्टिकोण से, यह फैसला त्योहारी सीजन में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक आवश्यक और सामयिक 'बूस्टर डोज' की तरह दिखाई देता है। परंतु, इस सिक्के का दूसरा पहलू राजकोषीय स्वास्थ्य और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दबाव से जुड़ा है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत तक सीमित रखने का एक बेहद महत्वाकांक्षी और अनुशासित लक्ष्य रखा है। ऐसे समय में, जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण देश के निर्यात और राजस्व प्राप्ति पर दबाव बना हुआ है, तब खजाने पर करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का यह अतिरिक्त वार्षिक भार राजकोषीय अनुशासन की राह को कठिन बना सकता है। यह अतिरिक्त खर्च सरकार को विकासोन्मुखी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि रेलवे, राजमार्गों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से अपने संसाधनों को मोड़ने पर मजबूर कर सकता है। अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत बताते हैं कि जब सरकार राजस्व व्यय (जैसे वेतन, पेंशन और भत्ते) पर अधिक खर्च करती है, तो उसका पूंजीगत व्यय पर सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।

आवास योजना के...

डॉ0 सीमा गुप्ता

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से साकार हो रहा पक्के घर का सपना

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद रामपुर में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन, वंचित और आवासविहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा तथा पक्की छत उपलब्ध कराने का अभियान निरंतर गतिशील है। एक पक्का घर केवल ईंट-गारे से निर्मित ढांचा भर नहीं होता, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य की ठोस बुनियाद होता है। जिले के ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से कच्चे एवं असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। जनपद रामपुर के विकास खण्ड बिलासपुर की ग्राम पंचायत मानपुर ओझा निवासी रिया सरकार (पत्नी असित सरकार) का परिवार इस प्रभावी बदलाव के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। योजना से जुड़ने से पूर्व यह परिवार एक कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच जीवनयापन कर रहे इस परिवार के लिए स्वयं के व्यय पर पक्का मकान निर्मित करा पाना अत्यंत कठिन था। कच्चे मकान में रहने के कारण परिवार को विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गंभीर समस्याओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। मूसलाधार बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने, सीलन आने और कच्ची दीवारों के ढहने की निरंतर आशंका बनी रहती थी। मौसम की प्रतिकूलता परिवार के दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थायी चिंता का कारण बन जाती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक सुरक्षित और टिकाऊ छत परिवार की प्राथमिक आवश्यकता थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत रिया सरकार को पक्के आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई। निर्धारित मानकों के अनुसार आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की किश्तें समय पर उपलब्ध कराई गईं। निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात परिवार को अपना नया और मजबूत पक्का मकान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी वर्षों पुरानी आवासीय असुरक्षा समाप्त हो गई।

पक्का मकान मिलने से परिवार को मौसमी आपदाओं और अनिश्चितताओं से स्थायी राहत मिली है। अब बरसात के दिनों में जलभराव या छत टपकने का भय नहीं रहता और परिवार पूरी निश्चिंतता एवं सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है।

पक्के आवास ने परिवार को न केवल आपदा-सुरक्षित आश्रय दिया है, बल्कि उनमें स्थायित्व, खुशहाली और भविष्य को संवारने का नया आत्मविश्वास भी जगाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी पात्र परिवारों को सर्वऋतु अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो बेघर हैं अथवा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। महिलाओं के नाम पर अथवा संयुक्त स्वामित्व में आवास आवंटन की व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में महिला सशक्तीकरण को भी नई दिशा दी है। सम्पत्ति का मालिकाना हक मिलने से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक रुतबे, निर्णय लेने की क्षमता और सुरक्षा की भावना में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सुरक्षित घरेलू परिवेश से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दीर्घकालिक सकारात्मक असर पड़ रहा है।

जरा हटके

प्रियंका सोनकर की...

बी0एल0 यादव

स्वयं सहायता समूह की सदस्या ने डिजिटल ज्ञान से उद्यम स्थापित कर चप्पल निर्माण से संवारी अपनी तकदीर

दृढ़ इच्छाशक्ति, सीखने की ललक और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता की नई राह बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कड़ा विकासखंड स्थित सैनी गांव की प्रियंका सोनकर ने अपने परिश्रम और डिजिटल ज्ञान के बल पर इसे सच कर दिखाया है। कभी परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली प्रियंका आज चप्पल निर्माण का उद्यम संचालित कर न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि आठ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। उनकी सफलता ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार के माध्यम से दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने की प्रेरक मिसाल है। कक्षा 12 तक शिक्षित 28 वर्षीय प्रियंका के परिवार में छह सदस्य हैं और उनकी तीन बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी तथा नियमित आय का कोई बेहतर साधन भी उपलब्ध नहीं था। घरेलू जिम्मेदारियों के बीच परिवार की जरूरतों को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने ऐसा काम शुरू करने का संकल्प लिया, जिसे घर की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाया जा सके और जिससे नियमित आमदनी भी हो। प्रियंका के जीवन में बदलाव की शुरुआत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद हुई। वह मां कड़ावासिनी स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनीं। बाला जी ग्राम संगठन और बढ़ते कदम महिला संकुल स्तरीय संघ से जुड़कर उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने तथा स्वरोजगार की संभावनाओं को समझने का अवसर मिला। समूह की बैठकों और उद्यमिता विकास परियोजना के अंतर्गत आयोजित सामुदायिक चर्चाओं ने उनके भीतर अपना व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास जगाया। प्रियंका ने पारंपरिक रास्ते पर चलने के बजाय डिजिटल माध्यम को अपना सीखने का साधन बनाया। यूट्यूब पर चप्पल निर्माण से संबंधित वीडियो देखकर उन्होंने चप्पल बनाने की प्रक्रिया, मशीनों, कच्चे माल और बाजार की जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद अपने स्तर पर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्होंने अपनी जमा पूंजी से एक लाख रुपये का निवेश किया और चप्पल निर्माण की एक मशीन लगाकर अपना उद्यम शुरू कर दिया। चप्पल निर्माण के लिए प्रियंका रबर शीट, सोल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, पट्टी और गोंद आदि का उपयोग करती हैं। इन सामग्रियों की प्रमुख आपूर्ति कानपुर से होती है। शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ उनका कारोबार धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। उद्यमिता विकास परियोजना के अंतर्गत आयोजित बैठकों में प्रियंका ने अपने व्यवसाय की जरूरतों को सामने रखा। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की टीम के सहयोग से उन्हें बढ़ते कदम महिला संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहयोग से उन्हें कच्चा माल खरीदने और उत्पादन को व्यवस्थित करने में मदद मिली। साथ ही, उन्हें बैनर, विजिटिंग कार्ड, रजिस्टर, बही-खाता, उद्यम पंजीकरण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मार्गदर्शन भी मिला। इससे उनके व्यवसाय को व्यवस्थित स्वरूप देने और बाजार में अपनी पहचान बनाने में सहायता मिली। आज प्रियंका अपने उद्यम का संचालन आत्मविश्वास के साथ कर रही हैं। कच्चा माल खरीदने से लेकर उत्पादन की योजना बनाने, ऑर्डर लेने और ग्राहकों से बातचीत करने तक के महत्वपूर्ण निर्णय वह स्वयं लेती हैं। डिजिटल लेन-देन के लिए स्मार्टफोन और ऑनलाइन भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल कर उन्होंने अपने काम को समय के अनुरूप बनाया है। उनके उद्यम से वर्तमान में आठ लोग जुड़े हुए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रियंका की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी आय में हुआ उल्लेखनीय बदलाव है। उद्यम शुरू करने से पहले उनकी मासिक आय लगभग चार हजार रुपये थी। चप्पल निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के बाद यह बढ़कर लगभग बीस हजार रुपये प्रतिमाह हो गई है। इस प्रकार उनकी वार्षिक आय लगभग 2.40 लाख रुपये तक पहुंच गई है। बढ़ी हुई आय से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक आर्थिक आत्मविश्वास मिला है। प्रियंका अब अपने कारोबार को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें एक अतिरिक्त चप्पल निर्माण मशीन और लगभग एक लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इससे वह उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अधिक ऑर्डर पूरे करने, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और अपने उत्पादों की बाजार तक पहुंच मजबूत करने की उम्मीद रखती हैं। प्रियंका सोनकर की कहानी बताती है कि डिजिटल ज्ञान, स्वयं सहायता समूहों का सहयोग, उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण और समय पर वित्तीय सहायता ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने यूट्यूब से जानकारी लेकर अपने उद्यम की नींव रखी, स्वयं सहायता समूह के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया और अपने परिश्रम से रोजगार सृजन का माध्यम बनाया। उनकी यात्रा इस विश्वास को मजबूत करती है कि अवसरों को पहचानने और निरंतर प्रयास करने वाली महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया नवीनीकृत बजट वेबसाइट का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश की बजट संबंधी जानकारी अब एक क्लिक पर

- बजट, वित्तीय आंकड़े, शासनादेश और महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
- चैटबॉट की सुविधा से बजट संबंधी सवालों के जवाब पाना होगा आसान

शुभारंभ

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट और वित्तीय जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए अपनी बजट वेबसाइट को नए रूप में लॉन्च किया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवीनीकृत वेबसाइट budget.up.nic.in का शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बजट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय आंकड़े, नियमावली, शासनादेश और अन्य उपयोगी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार के अनुसार, वेबसाइट को आमजन, शोधकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बजट संबंधी सूचनाओं तक पहुंच आसान बनाना और राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नवीनीकृत वेबसाइट की प्रमुख विशेषताओं में चैटबॉट सुविधा शामिल है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता बजट से जुड़े प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे बजट के दस्तावेजों और वित्तीय आंकड़ों को समझने में लोगों को मदद मिलने की उम्मीद है। वेबसाइट पर राज्य बजट के अलावा वित्तीय नियमों और व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, आकस्मिकता निधि नियमावली, विभिन्न रिजर्व फंडों में उपलब्ध धनराशि और उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 से संबंधित विवरण शामिल हैं। नवीनीकृत पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित शासनादेश उपलब्ध कराए गए हैं।

केंद्र से मिलने वाले धन और राज्यांश की भी मिलेगी जानकारी

वेबसाइट पर केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली धनराशि और केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का विवरण भी देखा जा सकेगा। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बजट में किए गए अनुदान संबंधी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय निकायों के बजट प्रावधानों और केंद्र से मिलने वाले वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करना आसान होगा।

पोर्टल पर पिछले 10 वर्षों के वित्त मंत्रियों के बजट भाषण भी रखे गए हैं। इससे शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, पत्रकारों और आम नागरिकों को अलग-अलग वर्षों के बजट प्रस्तावों तथा वित्तीय प्राथमिकताओं का अध्ययन करने में सुविधा मिल सकती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसले देश के विकास

आत्मनिर्भरता और जनकल्याण को देंगे नई गति : श्री केशव प्रसाद मौर्य

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इन निर्णयों से खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन-भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। ये फैसले विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मौर्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,856.67 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, भारतीय निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने तथा खेल उपकरणों के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति देने में सहायक होगी। इससे देश में खेल सामग्री निर्माण के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ के परिव्यय वाली 'कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना' (CMPS) को मंजूरी मिलना भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से देश में कंटेनर निर्माण की क्षमता का विस्तार होगा, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। इसके साथ ही निवेश, तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती प्राप्त होगी।

फास्ट न्यूज

5 लाख रुपए मांगने पर महिला की हुई थी हत्या

दुबग्गा। लखनऊ में सैदपुर अंडरपास के पास मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पांच लाख रुपए वापस मांगने और शादी का दबाव बनाए जाने से बचने के लिए हत्या की साजिश रची गई थी। वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार समेत सामान बरामद किया गया है।

करवा-चौथ पर मेहंदी लगाकर सड़क पर उतरीं नर्सें

लखनऊ। लखनऊ में गुरुवार को करवा चौथ के दिन नर्सों ने दो घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में मेहंदी लगाकर और दुल्हन की तरह सज-संवर-कर महिलाएं प्रदर्शन में पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उनका यह प्रदर्शन करवा चौथ पर चांद देखने की परंपरा से जुड़ा था। राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि आज यह प्रदर्शन बलरामपुर अस्पताल समेत प्रदेश के सभी अस्पतालों में हो रहा है।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिला कैशलेस इलाज

लखनऊ। लखनऊ में गुरुवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के निर्णय का स्वागत किया है।
जेएन तिवारी ने कहा कि इस निर्णय से बेसिक, प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, उन्होंने बताया कि बेसिक और प्राथमिक स्तर के 1.70 लाख तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1.22 लाख और माध्यमिक विद्यालयों के 48 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र ने बदली उप्र की तस्वीरः मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 2017 के पश्चात सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई संपर्क की अभूतपूर्व बढ़ोतरी से अवगत कराया

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' के जरिये प्रदेशवासियों को 2017 के पश्चात सड़क, रेल, मेट्रो व एयर कनेक्टिविटी की अभूतपूर्व बढ़ोतरी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क केवल दूरियां नहीं घटाते, बल्कि ये सुविधा, समय की बचत और समृद्धि की नई संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की इन जीवन रेखाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र से इस तस्वीर को बदला है।

भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने से पहले देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में मात्र डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। आज प्रदेश में 10 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। तब हवाई सेवाएं चुनिंदा शहरों तक सिमटी थीं, लेकिन आज 12 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्रदेश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। तब प्रदेश के एक भी शहर में मेट्रो नहीं चलती थी। वहीं, आज 7 शहरों में मेट्रो जनजीवन को नई गति दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परिवर्तन से किसान की उपज को बड़ा बाजार और उद्यमिता को नए अवसर मिल रहे हैं। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार तक पहुंच सुगम हो रही है। कामकाजी लोगों का समय बच रहा है। पर्यटन का विस्तार भी हो रहा है, जिससे स्थानीय परिवारों की आजीविका को नई शक्ति मिल रही है।

विकास की यह गति आज गांव से कस्बे और कस्बे से शहर तक नागरिकों के जीवन को बदल रही है। हर क्षेत्र को अवसर, हर उद्यम को सामर्थ्य और हर परिवार के जीवन में बढ़ती खुशहाली 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की नई पहचान है। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार तक पहुंच सुगम हो रही है। कामकाजी लोगों का समय बच रहा है। पर्यटन का विस्तार भी हो रहा है, जिससे स्थानीय परिवारों की आजीविका को नई शक्ति मिल रही है।

दिव्यांगजन द्वारा निर्मित सामग्री के प्रदर्शन व बिक्री हेतु

लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश भर में मंडल स्तर पर दीपावली मेले के आयोजन की पहल की गई है। श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में विगत माह इस संबंध में हुई बैठक में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए प्रदेश के प्रत्येक मंडल स्तर पर दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित सामग्रियों के प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु दीपावली मेले आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत लखनऊ मंडल को छोड़कर प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर मेले के आयोजन के लिए 3.00 लाख तथा लखनऊ मंडल में कार्यक्रम के आयोजन हेतु 7.00 लाख की धनराशि निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त उपनिदेशकों एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट आर.बी. थापा के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ने जताया शोक

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट आरबी थापा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरबी थापा का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से घटनाओं को दर्ज करने के साथ ही समाज, समय और बदलते दौर की महत्वपूर्ण तस्वीरों को इतिहास का हिस्सा बनाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आरबी थापा की तस्वीरें केवल समाचारों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें संवेदना, दृष्टि और मानवीय सरोकार भी दिखाई देते थे। एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने अपने कैमरे से घटनाओं और परिस्थितियों को इस तरह सहेजा कि

वे समय के साथ इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। उन्होंने कहा कि फोटो पत्रकारिता में कैमरे की भूमिका केवल किसी घटना को दर्ज करने तक सीमित नहीं होती। एक संवेदनशील फोटो जर्नलिस्ट अपनी तस्वीरों के माध्यम से समाज की परिस्थितियों, लोगों की भावनाओं और समय के बदलाव को भी सामने लाता है। आरबी थापा ने अपने काम के जरिए इस भूमिका को निभाया।

सतीश महाना ने कहा कि आरबी थापा ने अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में कई समाचार संस्थानों के साथ काम किया और अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनका सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और काम के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबी थापा का जाना केवल एक अनुभवी फोटो पत्रकार का निधन नहीं है, बल्कि उस संवेदनशील दृष्टि का भी जाना है, जो अपने कैमरे के जरिए समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को तस्वीरों में सहेजती थी। ऐसी तस्वीरें आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की घटनाओं और परिस्थितियों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आरबी थापा की स्मृतियां और उनके द्वारा खींची गई अर्थपूर्ण तस्वीरें पत्रकारिता जगत में सदैव जीवंत रहेंगी। उनके कार्य को लंबे समय तक याद किया जाएगा।

सतीश महाना ने शोक संतप्त परिवार के साथ-साथ आरबी थापा के मित्रों, सहयोगियों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और शक्ति मिलने की कामना की।

लखनऊ में 30 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे

पीईटी परीक्षा के चलते डीआईओएस ने जारी किया आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में PET परीक्षा के चलते 30 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इनमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की PET परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को आयोजित की जा रही है। लखनऊ में परीक्षा के लिए 45 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में करीब 20 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। उनके साथ अभिभावकों के आने से शहर में भीड़ बढ़ने की आशंका है।

दीपावली पर अनावश्यक शटडाउन और बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं : ऊर्जा मंत्री

योगी सरकार का त्योहारों पर तोहफा, दीपावली-छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली

- बकाया वसूली के नाम पर त्योहारों में कनेक्शन काटकर उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए
- जहां जरूरत हो, वहां ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार तत्काल किया जाएः ऊर्जा मंत्री

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ,। दीपावली, छठ और अन्य त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए इस दौरान अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा जाए। इसके लिए जरूरी तैयारियां समय से पूरी की जाएं, ताकि लोगों को दीपावली और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने अनावश्यक रूप से बिजली बंद करने और बार-बार आपूर्ति बाधित होने की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय बकाया बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और बिजली विभाग की कार्रवाई से पर्वों की तैयारियों पर असर न पड़े। ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी के मामलों में कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए।

झटपट पोर्टल के आवेदनों का तत्काल हो निस्तारण

ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन को लेकर अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या न झेलनी पड़े। जहां जरूरत हो, वहां ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार तत्काल किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत परउपभोक्ताओं को बधाई दी।

इससे घरेलू, व्यावसायिक सहित अन्य श्रेणियों को लगातार पांचवें महीने सीधा लाभ मिलेगा। नवसृजित नगर पंचायतों की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने को नगर विकास विभाग तैयार है, इसलिए विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी सहित विद्युत विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई : तत्काल जांच कर दोषी पाए जाने पर अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा सख्त

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की जनसुनवाई में बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। लखनऊ के एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। बाद में संबंधित सहायक अभियंता पर कनेक्शन देने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में लखनऊ निवासी विद्युत उपभोक्ता अभिनव त्रिपाठी ने अपने घरेलू बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्या रखी। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने फरवरी 2026 में तीन किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग की ओर से एक मार्च 2026 को 11,622 रुपये का स्टीमेट जारी किया गया, जिसे उन्होंने जमा भी कर दिया। उपभोक्ता का आरोप है कि निर्धारित रकम जमा करने के बावजूद उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। इसके बाद मामले में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने संबंधित सहायक अभियंता शुभम सिंह पर कनेक्शन देने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार, रिश्वत नहीं देने पर 12 अक्टूबर 2026 को करीब 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट जारी कर दिया गया। उपभोक्ता ने जनसुनवाई में इस पूरे मामले को उठाते हुए कार्रवाई की मांग की।

फिलहाल रिश्वत मांगने और नया स्टीमेट जारी किए जाने को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्षता से जांच कर तथ्य सामने लाए जाएं और जिम्मेदारी तय की जाए। उपभोक्ता की शिकायत सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कराने और शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को परेशान करना, उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना और सरकारी सेवाओं के बदले रिश्वत मांगने जैसी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान पेयजल, अतिक्रमण, बिजली कनेक्शन, विद्युत बिल में सुधार और नए बिजली सबस्टेशन की स्थापना सहित नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। किसी उपभोक्ता को बिना उचित कारण परेशान करना या उसके काम को जानबूझकर लंबित रखना गंभीर लापरवाही है।

त्योहारों पर घटतौली और एमआरपी से अधिक वसूली रोकने के लिए यूपी में जांच अभियान

मिठाई, गैस सिलेंडर, तेल-घी से लेकर आटा और सोने-चांदी के तराजू तक की जांच

- 26 अक्टूबर से लगातार जारी है सघन पड़ताल; 31 अक्टूबर तक चलेगा प्रथम चरण का अभियान
- मिठाई, गिफ्ट पैक, एलपीजी, खाद्य तेल, आटा-मैदा, ज्वैलर्स एवं पेंट प्रतिष्ठानों पर विभागीय टीमों का सख्त पहरा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को घटतौली और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। विधिक माप विज्ञान विभाग की टीमें मिठाई की दुकानों, किराना प्रतिष्ठानों, गैस सिलेंडरों

के वितरण केंद्रों, सराफा बाजार और अन्य दुकानों पर जांच कर रही हैं। अभियान का उद्देश्य तौल में गड़बड़ी, पैकेट में कम सामान देने और डिब्बाबंद वस्तुओं पर अधिक कीमत वसूलने जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाना है। विभाग के अनुसार, यह अभियान 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ है। पहले चरण में 31 अक्टूबर तक जांच की जाएगी, जबकि दूसरे चरण का अभियान 2 से 5 नवंबर तक चलेगा। नियंत्रक विधिक माप विज्ञान अमनदीप डुल्ली के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमें नियमित जांच के साथ बाजारों में औचक निरीक्षण भी कर रही हैं। त्योहारों के दौरान जिन वस्तुओं की मांग अधिक रहती है, उन्हें जांच के लिए प्राथमिकता दी गई है। विभाग की टीमें छह प्रमुख क्षेत्रों में तौल, पैकेजिंग, घोषित मात्रा और मूल्य से संबंधित नियमों का सत्यापन कर रही हैं। दीपावली पर मिठाइयों और गिफ्ट पैक की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में मिठाई के साथ इस्तेमाल होने वाले डिब्बे के वजन को भी तौल में शामिल करके ग्राहक से अधिक पैसे वसूलने की आशंका को देखते हुए जांच की जा रही है। इसके अलावा गिफ्ट हैंपर्स पर दर्ज घोषणाओं और संबंधित विवरणों का भी सत्यापन किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडरों में गैस की वास्तविक मात्रा की जांच भी अभियान का हिस्सा है।

आगरा मे 59 निजी विद्यालयों को बंद करने का आदेश

अमान्य स्कूल्स पर एक-एक लाख जुर्माना, बीएसए ने कार्रवाई की

कार्रवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। जिले में बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने वालों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने छह विकास खंडों में संचालित 59 अमान्य विद्यालयों को बंद कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राकेश सिंह ने संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों को जुर्माने की वसूली कराने और विद्यालयों का संचालन बंद कराने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई पूरी होने के बाद अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। विभाग की जांच में सामने आया कि जिले के अलग-अलग विकास खंडों में कई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे। इन विद्यालयों को चिह्नित करने के बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चिह्नित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जल्द पूरी कराएं।

बाह में सबसे ज्यादा 15 अमान्य स्कूल मिले

बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में जिले के छह विकास खंडों में कुल 59 अमान्य विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें बाह विकास खंड में सबसे ज्यादा 15 स्कूल बिना मान्यता के संचालित मिले हैं। इन विद्यालयों के खिलाफ भी बंद कराने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से सभी चिह्नित विद्यालयों के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, बाकी पांच विकास खंडों में कितने-कितने स्कूल चिह्नित किए गए हैं, इसका विस्तृत ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

हर स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना

बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिह्नित विद्यालयों से जुर्माने की धनराशि वसूल की जाए। इसके साथ ही इन स्कूलों का संचालन बंद कराया जाए। अधिकारियों को कार्रवाई पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। विभाग का उद्देश्य बिना मान्यता संचालित हो रहे विद्यालयों पर रोक लगाना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन कराते हुए जुर्माने की वसूली और स्कूल बंद कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रावधानों के विपरीत है। इसी के तहत अमान्य विद्यालयों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए इसकी प्रगति से अवगत कराएं। अब देखना होगा कि चिह्नित 59 विद्यालयों को बंद कराने और जुर्माने की वसूली की कार्रवाई कितनी जल्दी पूरी होती है।

6 दिन बाद भी नहीं भरा गहरा गड्ढा

500 मीटर के दायरे में 3 स्कूल, यूनिवर्सिटी के पास हादसे का खतरा

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा के पालीवाल पार्क में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर हुआ गहरा गड्ढा 6 दिन बाद भी नहीं भरा गया है। 15 फीट लंबे और 10 फीट गहरे गड्ढे के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को हादसे का डर सता रहा है। 24 अक्टूबर को पाइपलाइन फटने से सड़क धंस गई थी। जलकल विभाग ने पाइपलाइन तो ठीक कर दी, लेकिन गड्ढे को भरने का काम अब तक नहीं हुआ है। गड्ढे से 500 मीटर के दायरे में 3 स्कूल हैं, जबकि करीब 50 कदम की दूरी पर आगरा यूनिवर्सिटी है।

सुबह टहलने आने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं। जलकल विभाग के मरम्मत कार्य कराने के बाद भी नगर निगमा ने गड्ढे को नहीं भरा है। जिससे लोगों को हादसे का डर सता रहा है। जलकल विभाग के मरम्मत कार्य कराने के बाद भी नगर निगमा ने गड्ढे को नहीं भरा है। जिससे लोगों को हादसे का डर सता रहा है। पालीवाल पार्क में 24 अक्टूबर को पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क धंस गई थी। इससे मौके पर करीब 15 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जलकल विभाग ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दी, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी गड्ढा नहीं भरा गया है।

फास्ट न्यूज

मथुरा में युवक की गोली मारकर हत्या

मथुरा। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के महोली गांव में बुधवार रात शराब के नशे में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

आरोप है कि मोहल्ले के ही विकास उर्फ विशाल ने रोहतास को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया।

वीआईपी पार्टी नेताओं की स्कॉर्पियो का शीशा टूटा

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेताओं की स्कॉर्पियो का संदिग्ध अवस्था में शीशा टूट गया। नेताओं ने गाड़ी पर फायरिंग का दावा किया। पुलिस की शुरुआती जांच में सड़क से गिट्टी उछलकर शीशे से टकराने की बात सामने आई है। गाड़ी में सवार चारों नेता सुरक्षित हैं। घटना कोतवाली नगर के पांचोपीरन स्थित नवीन बाधमंडी के पास हुई। VIP के प्रदेश सचिव संजय पासवान, जिन्हें जिले का प्रभारी बनाया गया है, जिलाध्यक्ष उर्मिला निषाद और दो अन्य नेता स्कॉर्पियो में सवार थे।

फतेहपुर में युवक अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार

फतेहपुर। फतेहपुर के बकेवर में पुलिस ने 105 किलो 400 ग्राम अवैध पटाखों के साथ 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया। पटाखे एक निर्माणाधीन मकान से मिले। पुलिस के मुताबिक, दीपावली और धनतेरस से पहले जिले में अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अपहरण-हत्या के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। जमुनापार पुलिस ने अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ विष्णु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ विष्णु निवासी गांव सिहोरा, थाना जमुनापार को बृहस्पतिवार सुबह 10:53 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 106 की सर्विस रोड पर पानी गांव स्थित अल्लैहपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामद कार का पंजीकरण नंबर यूपी 85 सीएन 8548 है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ जमुनापार थाने में हत्या, अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

इसके अलावा वर्ष 2024 में भी उसके खिलाफ मारपीट, धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजयपाल सिंह राघव, उपनिरीक्षक प्रवीण शर्मा, कांस्टेबल राजकुमार, मनीष कुमार और महिला कांस्टेबल सारिका शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की है।

प्रयागराज में 5 करोड़ कैश जमीन में गड़ा मिला

3 नीले ड्रमों में भरी थीं 500-500 के नोटों की गड्डियां, 40 पुलिसवालों ने घर घेरा

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। प्रयागराज में जमीन के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए गड़े मिले। यह रकम 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों के रूप में तीन नीले ड्रमों में भरी थीं। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। वहीं, आयकर विभाग की टीम आज (29 अक्टूबर) इन नोटों की गिनती करेगी। मामला जिला मुख्यालय से 32KM दूर रामनगर गांव का बुधवार का है। पुलिस के मुताबिक, घर की तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे गए 3 नीले ड्रम मिले। इसमें कपड़े से कवर करके नोटों की गड्डियां रखी गई थीं। पुलिस ने कैश को कब्जे में लेकर सील कर दिया और घर की घेराबंदी कर दी। इस दौरान सोरांव के एसीपी श्यामजीत प्रमिला सिंह भी मौजूद रहे। करीब साढ़े 4 घंटे तक घर में सर्च अभियान चलाने के बाद पुलिस साढ़े 10 बजे लौट गई। पुलिस ने राकेश यादव के भाई बबलू को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पूरे परिवार को पुलिस टीमें अपने साथ ले गई हैं। अभी भी घर के चारों तरफ 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। घर के साथ उसके बाग और खाली जमीन पर भी पुलिस ने रिबन बांध दिया है। इस मामले में थाने के एक दरोगा जांच करने पहुंचे थे। उनसे राकेश यादव की हॉट टॉक हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तो घर के अंदर करोड़ों रुपए छिपाने की कहानी सामने आई। दो ट्रैक्टर के साथ DJ और पिकअप खरीदा। फिर यहीं पर सीमेंट-सरिया का कारोबार करने लगा।

पुलिस ने गांव की बिजली काटकर मारी रेड

नवाबगंज इलाके के बरईपुर गांव में राकेश यादव उर्फ महाकाल का पुश्तैनी मकान है। पुलिस को राकेश के घर में चोरी के रुपए जमीन में गाड़कर रखने का इनपुट मिला था। यह बात पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया तक पहुंची। इसके बाद बुधवार शाम 6 बजे डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार और एडीसीपी गंगानगर पुष्कर वर्मा समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले पुलिस ने पूरे गांव की बिजली कटवा दी। फिर सर्च अभियान शुरू किया।

गांववालों का दावा- कुछ साल में खरीदी गई 22 बीघा जमीन

गांववालों ने बताया- राकेश यादव कई साल पहले पुणे में अपने बहनोई और साले के साथ रहकर एक सर्राफा व्यापारी के घर काम करता था। कोविड के समय वह घर चला आया। इसके बाद उसने 22 बीघा जमीन खरीदी। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। फिर करीब 1 करोड़ रुपए लगाकर घर बनवाया। दो ट्रैक्टर के साथ DJ और पिकअप खरीदा। फिर यहीं पर सीमेंट-सरिया का कारोबार करने लगा।

आगरा लेबर कमिश्नर कार्यालय में हंगामा

जूता फैक्ट्री के मजदूरों को पीएफ और ईएसआई का पैसा नहीं मिला, वेतन भी कम दे रहे

तमसा संकेत, एजेंसी

सदर। सदर स्थित ग्लोबल शू फैक्ट्री में मजदूरों को निर्धारित वेतन से कम सैलरी देने का मामला सामने आया है। मजदूरों का आरोप है कि श्रम विभाग के नियमानुसार उन्हें 26 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से केवल 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस तरह हर महीने 14 हजार रुपये का अंतर होने से मजदूरों में नाराजगी है। मामले को लेकर गुरुवार को सैकड़ों मजदूरों ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में सदर माल रोड स्थित लेबर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और फैक्ट्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने मांग की कि उन्हें नियमानुसार पूरा वेतन दिलाया जाए और फैक्ट्री में श्रम कानूनों के पालन की जांच कराई जाए। शिकायत सुनने के बाद लेबर कमिश्नर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के वेतन रजिस्टर और संबंधित दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों का कहना है कि उन्हें श्रम विभाग के नियमों के अनुसार 26 हजार रुपये वेतन मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी की ओर से केवल 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक, निर्धारित वेतन और उन्हें मिल रही सैलरी के बीच हर महीने 14 हजार रुपये का अंतर है। उनका आरोप है कि कम वेतन मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, 26 हजार रुपये के वेतन निर्धारण का आधार और संबंधित श्रेणी में लागू न्यूनतम वेतन की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इस संबंध में श्रम विभाग की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने पहले फैक्ट्री मालिक से मिलकर निर्धारित वेतन देने की मांग की थी। उनका कहना है कि इस दौरान उनकी शिकायत पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसी वेतन पर काम करना है तो करें, अन्यथा नौकरी छोड़ दें। मजदूरों के मुताबिक, इस जवाब के बाद उन्होंने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह से संपर्क कर अपनी समस्या बताई। इसके बाद मामले को श्रम विभाग तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया।

3 साल से काम कर रहे रामबाबू, बोले- परिवार चलाना मुश्किल

फैक्ट्री में पिछले तीन साल से काम कर रहे मजदूर रामबाबू ने बताया कि महंगाई के दौर में 14 हजार रुपए महीने में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उनका आरोप है कि वेतन को लेकर अधिकारियों या प्रबंधन से शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है।

पीएफ, ईएसआई और ओवरटाइम का पैसा भी नहीं देने का आरोप

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में 300 से अधिक मजदूर काम करते हैं। आरोप है कि सभी को तय वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा पीएफ, ईएसआई और ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और मजदूरों की शिकायतों के बावजूद विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मजदूरों को उनका पूरा हक दिलाने की मांग की।

जिला कारागार में बंद महिलाओं को करवाचौथ की सामग्री वितरित

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति ने साड़ी

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। करवाचौथ के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की ओर से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध महिलाओं को साड़ी, शृंगार सामग्री, करवे और कैलेंडर सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। समिति ने इस पहल के माध्यम से महिलाओं के बीच त्योहार की खुशियां बांटने का प्रयास किया।

समिति के चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में जेल अधीक्षक अंशुमान गर्ग ने समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपराध निरोधक समिति समय-समय पर जेल प्रशासन के साथ मिलकर सहयोगात्मक कार्य करती है। इसके लिए उन्होंने समिति के सदस्यों का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे कार्य जारी रखने की अपेक्षा की। समिति के आगरा मंडल सचिव कपिल देव शर्मा ने कहा कि समिति जेल में निरुद्ध बंदियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है और आगे भी हरसंभव सहयोग करती रहेगी। जिला सचिव सूर्य भानु प्रताप पांडेय ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जिला सचिव का पदभार ग्रहण किया है। आगामी दिनों में जेल प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन के कार्यों में भी सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में जेलर सुरेंद्र मोहन, वरिष्ठ लेखाकार सीएम तिवारी, आचार्य शिवम गौड़, आचार्य कृष्ण चंद शास्त्री सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पृष्ठ 01 का शेष...

बैंक डिजिटल अरेस्ट...

अपराधी भारी डिस्काउंट, पार्सल डिलीवरी, बैंक अलर्ट, केवाईसी अपडेट और बिजली बिल के नाम पर फर्जी मैसेज भेज सकते हैं। एसएमएस, वॉट्सएप और ईमेल से भेजे लिंक से निजी जानकारी चुराई जा सकती है। फर्जी एप पासवर्ड-ओटीपी भी चुरा सकते हैं। बचने के लिए अनजान लिंक न खोलें, संदिग्ध एप इंस्टॉल न करें और भुगतान या केवाईसी संबंधी संदेशों की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट या एप से ही करें।

पटाखों पर पूरे बैन के...

बेंच ने कहा, "जमीन पर लागू किए बिना आदेश और निर्देश देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं हुआ तो यह मजाक बन जाएगा।" ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दिल्ली सरकार और CAQM प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। नवंबर से कई उपाय लागू होंगे। इनमें पुराने वाहनों पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर नियंत्रण और दिल्ली में दफ्तरों के समय में बदलाव शामिल है। भाटी ने कहा, "हम प्रदूषण के उस मौसम से निपटने के लिए तैयार हैं, जो दुर्भाग्य से हर साल आता है।" केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर आंतरिक चर्चा जारी है। भाटी ने इस चर्चा को पूरा करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा, "बेरियम के मुद्दे पर हमारी आंतरिक चर्चा पूरी नहीं हुई है।" बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर तीन हफ्ते बाद विचार करेगी। दरअसल, 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पटाखों के अलावा पराली जलाने और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। दूसरी याचिका पटाखों के निर्माण पर रोक से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहीं एमिकस क्यूरी वकील ने कहा कि पटाखे जलाने से बड़ी मात्रा में खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर (PM) निकलता है। यह मानव शरीर में जाकर फेफड़ों और दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते दशहरा के दौरान दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में बढ़ोतरी हुई। बिक रहे पटाखे वास्तव में ग्रीन पटाखे हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई आदेश दे चुका है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पटाखों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, एक अन्य वकील ने पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने का विरोध किया। 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पटाखों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह चौबीसों घंटे पटाखे जलाने की अनुमति नहीं देगा। बेंच ने कहा था कि बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इसके लिए पटाखे जलाने के तय समय निर्धारित किए जा सकते हैं। उस सुनवाई में भाटी ने एक नोट दिया था। इसमें CSIR-NEERI की सिफारिश के आधार पर कुछ खास नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइन्ड ग्रीन क्रैकर्स के लिए सीमित और सशर्त छूट पर विचार करने की बात कही गई थी। इन पटाखों को शोर, उत्सर्जन और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

कांग्रेस आज सड़क...

विपक्ष SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में CEC के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पब्लिक महाभियोग में जनता या राजनीतिक दल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ विरोध जताते हैं। पब्लिक महाभियोग की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार करेंगी। प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली का समर्थन किया है। CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी समर्थक रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शामिल हो सकते हैं। CJP ने INDIA ब्लॉक में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। इस पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है। INDIA ब्लॉक और CJP दोनों ही SIR और वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने का मार्च है। यह मार्च भारतीय संविधान और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। एक नवंबर का मार्च लोकतंत्र बचाने, वोट चोरी रोकने और संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि देश के लोकतंत्र, संविधान, विचारों और अपनी बात रखने की आजादी पर हमला हो रहा है तो उसे इस मार्च में शामिल होना चाहिए। INDIA ब्लॉक के नेता SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 से 13 अक्टूबर के बीच 8 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट ने भी 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस दौरान शहर में बैरिकेडिंग की गई थी, 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और 7 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

100% एथेनॉल...

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा, 'हमने कुछ अखबारों में पढ़ा कि 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को मंजूरी दी गई है।' बेंच ने पूछा, 'सैद्धांतिक तौर पर हम जानना चाहते हैं कि अगर 100% एथेनॉल वाली गाड़ियों की अनुमति दी गई है तो इसकी सप्लाई कैसे की जाएगी?' अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा।' सुनवाई के दौरान बेंच ने देश के किसानों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बड़े सार्वजनिक हित और पर्यावरण के नजरिए से भी इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, 'तीसरा मुद्दा देश की बड़ी आबादी यानी किसानों के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है।

आजम खान को...

वहीं, शिकायतकर्ता भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से अधिवक्ता शरद शर्मा और नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि दोषसिद्धि और सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं, यूपी सरकार ने दोनों की सजा सस्पेंड करने की मांग का विरोध किया था। सरकार ने अपनी याचिका में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की थी। आजम को बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 17 नवंबर, 2025 को कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 5 मई, 2026 को सरकार के वकील ने सजा बढ़ाने के लिए रामपुर की अपर कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सीबीएसई 2028...

वे स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन दे सकते हैं या बोर्ड परीक्षा देकर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। CBSE ने अपने सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इस फैसले से 9वीं और 10वीं को मिलाकर लगभग 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे।

स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट से बाहर

गर्दन में चोट, न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर में वापसी की उम्मीद

मुंबई। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ गर्दन में चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और निर्णायक टेस्ट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, एमआर-आई स्कैन में उनकी गर्दन के जोड़ में चोट की पुष्टि हुई है। गर्दन की मूवमेंट सीमित होने के कारण वह केपटाउन टेस्ट के लिए फिट नहीं थे। अब दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से उनकी वापसी की उम्मीद है। स्मिथ की जगह टीम में शामिल किए गए जॉश इंग्लिस ने तीसरे टेस्ट में नाबाद 85 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 330 रन बना लिए थे। टीम को साउथ अफ्रीका के 329 रन के स्कोर पर

1 रन की बढ़त मिल गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि स्मिथ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन गर्दन में दर्द हुआ था। इसके बाद उनका एमआरआई स्कैन कराया गया, जिसमें गर्दन के जोड़ में चोट का पता चला। बोर्ड के मुताबिक, स्मिथ का इलाज और रिहैबिलिटेशन जारी रहेगा। उन्हें दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है।

रैनशॉ बोले- इंग्लिस ने दबाव में अच्छी बल्लेबाजी की

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट रैनशॉ ने इंग्लिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंग्लिस प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। रैनशॉ के मुताबिक, लगातार दो विकेट गिरने के बाद टीम दबाव में थी। ऐसे समय में इंग्लिस ने सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि यह इंग्लिस की स्वाभाविक शैली के मुताबिक पारी थी और टीम को उस समय ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत थी।

इंग्लिस ने वापसी पर बनाए नाबाद 85 रन

स्मिथ के बाहर होने के बाद टीम में शामिल किए गए जोश इंग्लिस ने 111 गेंदों पर नाबाद 85 रन की पारी खेली। पिछले साल एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट के बाद यह उनका पहला टेस्ट मैच है। इंग्लिस ने उस समय पारी संभाली, जब ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी-जल्दी दो विकेट गंवा दिए थे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और एलेक्स कैरी के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, स्मिथ का इलाज और रिहैबिलिटेशन जारी रहेगा। उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से होने की उम्मीद है। ऐसे समय में इंग्लिस ने सकारात्मक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि यह इंग्लिस की स्वाभाविक शैली के मुताबिक पारी थी और टीम को उस समय ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत थी।

रणजी ट्रॉफी : मुंबई ने हरियाणा को फॉलोऑन दिया

मुशीर खान ने 6 विकेट लिए, तमिलनाडु ने रेलवे को 5 विकेट से हराया

मुंबई। रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड के मुकाबलों में मुंबई ने हरियाणा के खिलाफ मजबूत स्थिति बना ली है। मुंबई के स्पिन ऑलराउंडर मुशीर खान ने 85 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं तनुष कोटियन ने 3 विकेट झटके। हरियाणा की पहली पारी 270 रन पर सिमट गई। मुंबई ने पहली पारी में 430 रन बनाए थे। इस तरह टीम को 160 रन की बढ़त मिली और उसने हरियाणा को फॉलोऑन दे दिया।

हरियाणा के लिए निशांत सिंधु ने 105 रन की पारी खेली। तमिलनाडु ने चेन्नई में रेलवे को 5 विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 39 रन तक

3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद आंद्रे सिद्धार्थ ने अर्धशतक लगाकर पारी संभाली और टीम को जीत तक पहुंचाया। बंगाल के खिलाफ केरल की पहली पारी 141 रन पर सिमट गई। मोहम्मद शमी और प्रदीप्त प्रमाणिक ने 7 विकेट किए, जबकि शाहबाज अहमद ने 2 विकेट लिए। बंगाल ने पहली पारी में 350 रन बनाए थे, जिससे उसे 209 रन की बढ़त मिली।

महाराष्ट्र के खिलाफ गुजरात के आर्य देसाई ने अर्धशतक लगाकर टीम को बढ़त दिलाने में अहम योगदान दिया। महाराष्ट्र की पहली पारी में सौरभ नवाले ने 95 रन बनाए, लेकिन टीम 278/9 के स्कोर पर संघर्ष करती रही। गुजरात ने पहली पारी में 223 रन बनाए थे। पंजाब ने पहली पारी में 431 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम 350 से ज्यादा रन बना लिए है। पंजाब के लिए सलिल अरोड़ा ने 151 रन की पारी खेली। पंजाब के वियान मल्होत्रा ने गेंदबाजी में 15 रन देकर 4 विकेट लिए।

चोटिल फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ आखिरी 2 टी-20 से बाहर

फिशर टीम में शामिल, भारत सीरीज में 3-0 से आगे

मुंबई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के आखिरी 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। उनके दाएं पैर की पिंडली में चोट लगी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि मैट फिशर को टीम में शामिल किया गया है। सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा। फर्ग्यूसन को यह चोट 24 अक्टूबर को दूसरे मैच के दौरान लगी थी। स्कैन में मामूली खिंचाव की पुष्टि हुई है। उन्हें वापसी में करीब एक सप्ताह और लग सकता है। फर्ग्यूसन 2 मैच में एक विकेट ही ले सके हैं। तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। दूसरे मैच के दौरान उनके दाएं जांघ के अगले हिस्से में दर्द हुआ था।

उन्हें ठीक होने में एक से दो सप्ताह लग सकते हैं। हेनरी को पहले से तय वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आगामी वनडे सीरीज के लिए ब्लैककैप्स में लौटना था। NZC ने कहा कि वह अब भी तय कार्यक्रम के अनुसार वापसी कर सकते हैं। सेंट्रल स्टैग्स के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को न्यूजीलैंड ए टीम में बुलाया गया है। वह भारत ए के खिलाफ दूसरे मैच में फिशर की जगह लेंगे। काइल जैमीसन के तय वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वे वेलिंगटन में ही रहेंगे। वे शनिवार को फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे दौर में कैंटरबरी के लिए खेलने के लिए उपलब्ध हैं। जैमीसन सोमवार को वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम से दोबारा जुड़ेंगे। मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फर्ग्यूसन और हेनरी 4 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज में खेलेंगे। वॉल्टर ने कहा, 'हम लॉकी और मैट के लिए निराश हैं। इंटरनेश-नल क्रिकेट में चोटें खेल का हिस्सा हैं, लेकिन मैचों से बाहर होना आसान नहीं होता।'

विमेंस टीम ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया

तीसरे वनडे में स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने 5 विकेट लिए, इंडिया सीरीज 3-0 से जीती

मुंबई। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत ली। बुधवार को वडोदरा में वैष्णवी शर्मा ने पहली बार वनडे में 5 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 39.5 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में भारत ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। प्रतीका ने नाबाद 59 रन और शेफाली ने नाबाद 51 रन बनाए। भारतीय टीम ने इस दौरे पर टी-20 सीरीज भी 3-0 से जीती थी। जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही। भारतीय गेंदबाज सयाली सतघरे ने लॉरीन फिरी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। क्रांति गौड़ ने चिपो मुगेरी-तिरिपानो का विकेट लिया। तीसरे ओवर तक जिम्बाब्वे का स्कोर 12 रन पर 2 विकेट था। वैष्णवी शर्मा ने 10वें ओवर में

गेंदबाजी शुरू की। उन्होंने बेलव्ड बिजा को 1 रन पर आउट किया। इसके बाद मॉडेस्टर मुपाचिकवा को 37 रन पर स्टंप कराया। मुपाचिकवा ने 48 गेंदों पर 7 चौके लगाए। जोसफिन नकोमो और चिएद्जा धुरुरु ने पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर पारी संभालने की कोशिश की। हालांकि वैष्णवी ने धुरुरु को आउट कर यह साझेदारी तोड़ी। इसके बाद वैष्णवी ने मिशेल मावुंगा और न्याशा ग्वांजुरा को भी पवेलियन भेज दिया। उनके अलावा सतघरे और गौड़ ने भी 2-2 विकेट लिए।

पहली ही गेंद पर यास्तिका का विकेट गिरा

- भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 2 साल बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी कर रहीं यास्तिका भाटिया पहली गेंद पर आउट हो गईं। इसके बाद प्रतीका रावल और हरलीन देओल ने पारी को संभाला।
- हरलीन 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुईं। भारत ने 9वें ओवर में 59 रन पर दूसरा विकेट गंवाया। इसके बाद शेफाली वर्मा ने प्रतीका का साथ दिया। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए भारत को जीत दिला दी।
- शेफाली ने 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने 24 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की। यह महिला वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है।
- प्रतीका ने 56 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 50 गेंदों पर 74 रन की अटूट साझेदारी की। भारत ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच जीत लिया।

मनोरंजन

'आप गूंगे बनकर बैठ जाते हैं'

परेश रावल बोले- सबको अपनी राय रखने का हक

मुंबई। सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह के सरकार विरोधी बयान के बाद एक्टर पुनीत इस्सर उन पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सरकार पसंद नहीं है, तो चुनाव लड़कर उसे हराएं। मंगलवार को शाह ने खुद को गर्व से 'दिमागी नक्सल' बताया था। उन्होंने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और युवाओं का हौसला तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। पहली बात तो यह है कि नसीरुद्दीन शाह जी हमारे सीनियर हैं, हमारे टीचर रह चुके हैं, आदरणीय हैं और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब आप कोई बात

करते हैं, तो सिलेक्टिव बात नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया और हिंदुस्तान के कितने मुद्दों पर मूकदर्शक बने रहते हैं। आप गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, तब तो आप बात नहीं करते। आप हर चीज का जवाब एकतरफा देते हैं। आप लेफ्टिस्ट सोच और नक्सली विचारधारा वाले वामपंथियों की सोच के हिसाब से जवाब देते हैं।

तमन्ना ने अन्नू कपूर के कमेंट पर दिया रिएक्शन

बोलीं- मैं इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देती, एक्टर ने बॉडी पर दिया था आपत्तिजनक बयान

- तमन्ना भाटिया आखिरी बार फिल्म 'द वन' में नजर आई थीं। यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को रिलीज हुई थी।
- अन्नू कपूर ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें 'उत्सव', 'तेजाब', 'विक्की डोनर' और 'जॉली एलएलबी 2' शामिल हैं।

मुंबई। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अन्नू कपूर के 'दूधिया बदन' वाले कमेंट पर पहली बार रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसी बातों के बजाय अपने काम पर ध्यान देती हैं। एक इवेंट में तमन्ना से उनके रंग

और बॉडी पर हुई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया। एक्ट्रेस से यह भी पूछा गया कि क्या वह चाहती हैं कि दर्शक उन्हें सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस और बोल्ड इमेज से अलग देखें। उनसे हालिया फिल्मों को इमेज बदलने की कोशिश के तौर पर भी सवाल किया गया। तमन्ना ने कहा कि एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए सुनना जरूरी है। इसके साथ यह समझना भी जरूरी है कि किस बात को रखना है और किसे नजरअंदाज करना है

अन्नू कपूर ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी थी

अन्नू कपूर के कमेंट को लेकर उनकी ट्रोलिंग हुई थी। इसके बाद कपूर ने अपने कमेंट पर सफाई दी थी। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कपूर ने कहा था, "लोगों ने मुझे गालियां दीं, खूसट बूढ़ा और सठिया गया जैसी बातें कहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर मैं 'दूधिया बदन' कहता हूं, तो बवाल मच जाता है, लेकिन अगर यही बात इंग्लिश में 'मिल्की बॉडी' कही जाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती।" अपनी सफाई के दौरान अन्नू ने यह भी कहा था कि अगर तमन्ना भाटिया खुद उनसे इस बारे में पूछेंगी, तो वे अपनी बात पर कायम रहेंगे।

प्रभास की फिल्म फौजी का टीजर हटाने की मांग

सुभाष चंद्र बोस के पोते बोले- नेताजी के इतिहास से छेड़छाड़ हुई, पीएम मोदी से की शिकायत

मुंबई। एक्टर प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' के टीजर को लेकर विवाद बढ़ गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। चंद्र कुमार बोस ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म के टीजर को हटाने और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए टीजर में सुधार करने की अपील की है। मंगलवार को चंद्र कुमार बोस ने

सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजे गए पत्र की कॉपी साझा की। पत्र में उन्होंने टीजर के उस सीन पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडॉल्फ हिटलर से बातचीत करते हुए और प्रभास के काल्पनिक किरदार 'फौजी' का परिचय कराते दिखाया गया है। टीजर की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें नेताजी और हिटलर को एक काल्पनिक किरदार की तारीफ करते हुए दिखाया गया है।

चंद्र कुमार बोस ने राष्ट्रीय प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानियों के मामूली चित्रण पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतने संवेदनशील और आपत्तिजनक कंटेंट को पास कैसे कर दिया गया।

पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील, मेकर्स को दी सलाह

चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि फिल्म के टीजर को वापस लेकर, उसमें जरूरी सुधार के बाद ही दोबारा जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी के सम्मान से जुड़ी चिंताओं का समाधान कर दिया जाता है, तो उनकी ओर से अभिनेता प्रभास और 'फौजी' की पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म के निर्देशक हनु राघवपुडी मामले की गंभीरता को समझेंगे 23 अक्टूबर को अभिनेता प्रभास के 47वें जन्मदिन पर फिल्म 'फौजी' के मेकर्स ने 'फाइल नंबर 25' नाम से एक वीडियो टीजर जारी किया था। 1942 के बर्लिन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस क्लिप में दिखाया गया है कि नेताजी भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगने हिटलर से मिलते हैं।

वॉर-ड्रामा फिल्म है 'फौजी'

'फौजी' एक बड़े बजट की पीरियड वॉर-एक्शन फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन हनु राघवपुड़ी ने किया है। फिल्म में दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
हालांकि, विवाद गहराने के बावजूद फिल्म के मेकर्स और निर्देशक हनु राघवपुडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

स्पेन में ट्रेन हादसे में 68 मौतों के बाद हिंसा

लोगों ने पुलिस पर बोतलें-पटाखे फेंके, सिग्नल खराब होने से भिड़ी थीं हाईस्पीड ट्रेनें

बवाल

मैड्रिड, एजेंसी

स्पेन में दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर में 68 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने राजधानी मैड्रिड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते के इस्तीफे की मांग की है। कुछ लोगों ने उन्हें 'मौत का मंत्री' तक कहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। लोगों ने पुलिस पर बोतलें और पटाखे फेंके। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। ट्रेनों के टक्कर की घटना बुधवार की है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक रेल सुरक्षा सिस्टम में

खराबी आई थी जिसके बाद कंट्रोल सेंटर ने एक ट्रेन को दोबारा चलने की इजाजत दी। आगे पटरी पर खड़ी दूसरी ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। सिग्नल सिस्टम की खराबी ही हादसे की असली वजह थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने भी कहा है कि जांच के बाद हादसे की असली वजह सामने आएगी और जिम्मेदारी तय हो सकेगी। हादसे के बाद देश की रेल व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इस साल स्पेन में हुआ यह दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसमें लोगों की जान गई है। इसके पहले जनवरी में हुए हादसे में 46 लोगों ने जान गंवाई थी।

रात भर चला रेस्क्यू, लोगों की तलाश जारी

हादसे के बाद राहत और बचाव दल रातभर मलबे में फंसे लोगों की तलाश करते रहे। क्षतिग्रस्त ट्रेनों से शवों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बचावकर्मी हादसे की जगह पर लगातार काम करते रहे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने हादसे की जगह के पास से टीवी पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। सांचेज ने कहा कि जांच में अगर किसी की लापरवाही या सुरक्षा में कमी सामने आती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल हुए दोनों जानलेवा रेल हादसों की वजह अलग-अलग हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर रेल सुरक्षा के नियमों को और सख्त किया जाएगा।

उस समय पटरी के जोड़ में खराबी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई थी।

- मैड्रिड में परिवहन मंत्रालय के बाहर कई प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
- प्रदर्शनकारियों ने स्पेन के झंडे और सरकार से जवाबदेही की मांग वाले बैनर लेकर प्रदर्शन किया।

नेतन्याहू बहुमत से दूर, फिर भी सरकार बना सकते हैं

आइजनकोट के पास भी सत्ता में आने के 3 रास्ते

तेल अवीव, एजेंसी

इजराइल में 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इसके बाद भी सरकार बनाने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट, दोनों के गठबंधन बहुमत से दूर हैं। इजराइली संसद में 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटें चाहिए। हालांकि, नेतन्याहू इससे कम सीटें होने पर भी सरकार बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें 19 सीटों के साथ किंगमेकर बनकर उभरी अरब पार्टियों की जरूरत भी नहीं है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे गादी आइजनकोट गठबंधन की उम्मीदें भी कायम हैं। 48 सीटों में आगे चल रहे इस गठबंधन के पास सरकार बनाने के 3 रास्ते हैं। आइजनकोट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके

खेमे की 48 सीटें बहुमत से काफी कम हैं। अरब पार्टियों की 19 सीटें जोड़ने पर नेतन्याहू विरोधी खेमे के पास सैद्धांतिक रूप से 67 सीटें हो सकती हैं। लेकिन कई यहूदी दल अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन या समझौते के खिलाफ हैं। चुनाव के शुरुआती नतीजे आने के बाद तेल अवीव में याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट इजराइल का झंडा लहराते हुए। तस्वीर 28 अक्टूबर 2026 की है।

चुनाव के शुरुआती नतीजे आने के बाद तेल अवीव में याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट इजराइल का झंडा लहराते हुए। तस्वीर 28 अक्टूबर 2026 की है।

फास्ट न्यूज

कैप्टन मच्छर के सिर पर टांकों के कई निशान दिखे

अबू धाबी। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के सिर पर टांकों के कई निशान दिखे हैं। ब्रिटिश नेता टॉमी रॉबिन्सन ने उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। कैप्टन मच्छर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी सर्वोच्च सम्मानों में से एक 'जायद II- फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया है। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कैप्टन मच्छर को सम्मानित करते हुए गले लगाया।

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले बोल्सोनारो भागकर अमेरिका पहुंचे

ब्राजीलिया। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले दक्षिणपंथी नेता फ्लावियो बोल्सोनारो भागकर अमेरिका पहुंच गए हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक बोल्सोनारो की पत्नी और दो बेटियां भी उनके साथ मियामी पहुंची हैं। रॉयटर्स ने फ्लावियो के एक सहयोगी ने मंगलवार को उनके ब्राजील छोड़ने की पुष्टि की थी। सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। बोल्सोनारो को अमेरिका में राजनीतिक शरण मिल सकती है। फ्लावियो रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से हार गए थे।

करवा चौथ पर लैब में बने डायमंड की डिमांड

नई दिल्ली। आज करवा चौथ है और बाजारों में गहनों की खूब खरीदारी हो रही है। इस बार खदान से निकलने वाले असली हीरों के मुकाबले लैब-ग्रोन डायमंड यानी लैब में तैयार हीरों की काफी डिमांड है। लैब में बने हीरे असली हीरों से करीब 70% तक सस्ते मिलते हैं।

खास बात तो ये है कि इनकी चमक, मजबूती और बनावट में रत्ती भर भी फर्क नहीं होता।

होम लोन की ईएमआई हर महीने ₹5000 बढ़ाएं

20 लाख का लोन 20 साल की जगह 12 साल में खत्म होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

अगर आपने होम लोन लिया है या इस फेस्टिवल सीजन में लेने वाले हैं, तो थोड़ी सी समझदारी से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। बस हर महीने की EMI में ₹5000 एक्स्ट्रा जोड़कर देना होगा। इससे आपका ब्याज आधा रह जाएगा साथ ही लोन 5 से 8 साल पहले खत्म हो जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी मजबूत बना रहेगा। छोटे लोन अमाउंट पर समय की बड़ी बचतः 10 लाख और 15 लाख के लोन में 5000 एक्स्ट्रा देने पर लोन की अवधि लगभग आधी (8 से 10 साल) रह जाती है। बड़े लोन अमाउंट पर पैसों की बड़ी बचतः 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख के लोन में समय के साथ-साथ 12 लाख से 15 लाख तक के ब्याज की भारी बचत होती है।

EMI बढ़ाने से पहले हर कर्जदार को अपने बजट और वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहिए EMI बढ़ाने से पहले देखें कि आपकी मंथली आय और इमरजेंसी फंड पर कोई बुरा असर न पड़े। यह गणना पूरी लोन अवधि के दौरान 8.5% की स्थिर ब्याज दर मानकर की गई है। फ्लोटिंग रेट लोन में रेपो रेट घटने या बढ़ने पर आंकड़े बदल सकते हैं। अपनी कुल देनदारियों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी सर्टिफाइड एडवाइजर की सलाह लेकर ही फैसला लें।

2 दिन पहले यूनुस से छात्रों ने संपर्क किया, विदेशी न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने मदद की

बांग्लादेश में साजिश रचकर गिराई गई थी हसीना सरकार

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश में साजिश के तहत शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी। उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान ही छात्र नेताओं ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी थी कि उनके बाद देश की कमान कौन संभालेगा। यह दावा अंतरिम सरकार के सलाहकार रहे मोहम्मद यूनुस के पूर्व प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने किया है। आलम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छात्रों ने यूनुस से संपर्क करने में फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP के पत्रकार कादरुद्दीन शिशिर की मदद ली थी। वे चाहते थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएं।

हसीना सरकार के खिलाफ कैसे शुरू हुआ था आंदोलन?

बांग्लादेश में 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। वहां सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30% तक सीटें आरक्षित थीं। छात्रों का कहना था कि इससे आम युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के मौके कम हो रहे हैं। वे चाहते थे कि भर्ती में परीक्षा और योग्यता के आधार पर ज्यादा नौकरियां मिलें। इसी मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बदल गया। सरकार की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान करीब 1,400 लोगों की मौत हुई।

यूनुस की अंतरिम सरकार के बाद सत्ता में आए तारिक रहमान

यूनुस की अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराकर सत्ता चुनी हुई सरकार को सौंपना था। इसके लिए 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव हुए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बड़ी जीत हासिल की।

पार्टी ने संसद की 300 में से 209 सीटें जीतीं। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके सत्ता संभालने के साथ ही यूनुस की अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया।

अब देश लौटना चाहती हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 19 अक्टूबर 2026 को कहा था कि वे दिसंबर में अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश की मौजूदा तारिक रहमान सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, मार सकती है या टॉर्चर कर सकती है, लेकिन वे इन खतरों से नहीं डरतीं। हसीना ने कहा कि खतरा कितना भी हो, उन्हें इसकी परवाह नहीं है और उन्हें अपने देश लौटना ही है।

अमेजन ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम पर सबसे ज्यादा असर

नए एलेक्सा डिवाइसेज लॉन्च करने के दिन ही छंटनी का फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी

टेक और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने डिवाइसेज एंड सर्विसेज यूनिट से करीब 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने छंटनी की पुष्टि की है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छंटनी किन स्थानों पर की गई है और प्रभावित कर्मचारियों में कितने लोग किस टीम से जुड़े थे। यह छंटनी ऐसे समय में हुई है, जब अमेजन अपने डिवाइसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सेवाओं का विस्तार कर रही है। कंपनी ने हाल ही में नए किंडल ई-रीडर्स, टैबलेट्स और एलेक्सा आधारित पांच नए स्मार्ट डिवाइसेज लॉन्च किए हैं। ऐसे में एक तरफ कंपनी

नए उत्पाद बाजार में उतार रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला उसके संगठनात्मक बदलावों की ओर संकेत करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को बुधवार, 28 अक्टूबर की सुबह ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए नौकरी खत्म किए जाने की जानकारी दी गई। यह ईमेल अमेजन के डिवाइसेज एंड सर्विसेज यूनिट की एचआर वाइस प्रेसिडेंट चेरी रॉबिन्सन की ओर से भेजा गया था। ईमेल में बताया गया कि कंपनी ने अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की है। इस समीक्षा के बाद कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने अपने कामकाज की संरचना में बदलाव की जरूरत बताई। अमेजन के प्रवक्ता ने भी छंटनी की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी ने कुछ पदों को समाप्त करने का कठिन फैसला लिया है। यह कदम कामकाज को अधिक कुशल बनाने और कर्मचारियों की भूमिका को कंपनी के प्रोडक्ट रोडमैप के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेजन की डिवाइसेज एंड सर्विसेज यूनिट कंपनी के कई प्रमुख उत्पादों और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी है। इसमें किंडल ई-रीडर, फायर टैबलेट और एलेक्सा से संचालित स्मार्ट डिवाइसेज जैसे उत्पाद शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार की छंटनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

इजराइल चुनाव में विदेशी दखल का शक

चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए, 92% वोट गिने जा चुके, नेतन्याहू और आइजनकोट दोनों बहुमत से दूर

तेल अवीव, एजेंसी

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में विदेशी दखल की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग ने जांच एजेंसी 'शिन बेट' को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, एजेंसी एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को शक है कि कतर और तुर्किये से इजराइल और वेस्ट बैंक में पैसे भेजे गए। इनका इस्तेमाल अरब नागरिकों की फंडिंग के लिए किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दिन भी मतों की गिनती जारी है। अब तक 92.6% वोटों की गिनती हुई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्षी नेता आइजनकोट दोनों बहुमत से दूर हैं। अब तक नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें, जबकि विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, अरब

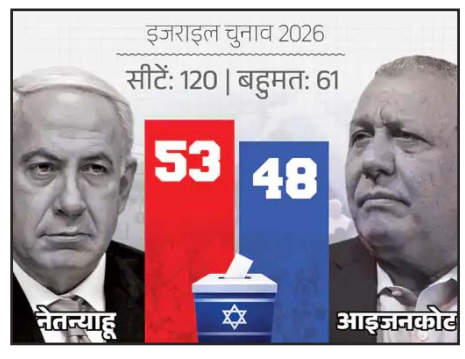

पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजराइल में इस बार सेना के जवानों ने 79.9% मतदान किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के मुताबिक, यह पिछली बार के मुकाबले 6.2% ज्यादा है। वहीं, इजराइल की जेल सेवा में मतदान 88.7% रहा, जो 2022 में 79% था। विदेशों में राजनयिक मिशनों पर तैनात इजराइली नागरिकों में से 86.7% ने वोट डाला। पिछली बार यह आंकड़ा 69.6% था। इन्हीं को डबल-एनवेलप बैलेट कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा वोट सेना के जवानों के होते हैं। ऐतिहासिक तौर पर उनके वोट अरब और अति-रूढ़िवादी पार्टियों के मुकाबले जायोनी पार्टियों को ज्यादा मिले हैं। डबल-एनवेलप बैलेट की गिनती गुरुवार सुबह शुरू हुई। इन बैलेट का इस्तेमाल उन लोगों के वोटों के लिए होता है, जो अपने तय मतदान केंद्र से अलग जगह पर वोट डालते हैं। इनमें सैनिक, राजनयिक, पुलिसकर्मी और विस्थापित लोग शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, सैन्य ठिकानों, अस्पतालों और जेलों में डाले गए इन वोटों से चुनावी नतीजों में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इस बार ऐसे करीब 5 लाख वोटों की गिनती होनी है, जो गुरुवार शाम तक पूरी हो जाएगी। पिछले चुनावों में भी इन वोटों का रुझान देशभर के नतीजों जैसा ही रहा है। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के 2021 के चुनाव विश्लेषण के मुताबिक, नेतन्याहू के गठबंधन को डबल-एनवेलप वोटों में 48.76% वोट मिले थे। आम वोटों में उसका हिस्सा 47.95% था। वहीं, विपक्षी पार्टियों को डबल-एनवेलप वोटों में 48.56% और आम वोटों में 50.06% वोट मिले थे। चुनाव समिति के कमांड सेंटर प्रमुख एलाद नवेह ने भी कहा कि इन वोटों का बंटवारा आमतौर पर देशभर में पड़े वोटों जैसा ही रहता है। दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, सोलबर्ग ने कहा कि उनके सामने विदेशी संस्थाओं की फंडिंग के जरिए चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के गंभीर संदेह आए हैं।

गिरावट: अक्टूबर में अब तक 6 हजार दाम गिर चुके, चांदी आज ₹2,945 नीचे आई

सोना ₹563 सस्ता होकर ₹1.42 लाख पर आया

नई दिल्ली, एजेंसी

दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार, 29 अक्टूबर को भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में कमी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 563 रुपये घटकर करीब 1.42 लाख रुपये रह गई। वहीं, एक किलो चांदी का भाव 2,945 रुपये गिरकर करीब 1.90 लाख रुपये पर आ गया। लगातार गिरती कीमतों के कारण सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों की बाजार पर नजर बनी हुई है। अक्टूबर महीने में अब तक सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने सोना करीब 6 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 30 हजार रुपये प्रति

किलो सस्ती हो चुकी है। इससे पहले सितंबर में भी दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। उस महीने सोना करीब 8 हजार रुपये और चांदी लगभग 15 हजार रुपये सस्ती हुई थी। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला सितंबर से ही देखने को मिल रहा है। 31 अगस्त को 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.56 लाख रुपये थी, जो 30 सितंबर तक घटकर लगभग 1.48 लाख रुपये रह गई। इस तरह सितंबर के दौरान सोने की कीमत में करीब 8 हजार रुपये की कमी आई।

असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीके

मैग्नेट टेस्टः असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।

आइस टेस्टः सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।

स्मेल टेस्टः असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आती है।

क्लॉथ टेस्टः चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें। अगर काला निशान आए तो असली है।

चांदी की कीमतों में भी इसी तरह गिरावट दर्ज की गई। 31 अगस्त को एक किलो चांदी का भाव करीब 2.37 लाख रुपये था, जो 30 सितंबर तक घटकर 2.22 लाख रुपये पर आ गया। यानी सितंबर में चांदी करीब 15 हजार रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। अक्टूबर में चांदी के भाव में सोने के मुकाबले अधिक गिरावट देखने को मिली है। महीने के दौरान चांदी करीब 30 हजार रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। वहीं, सोने की कीमत में लगभग 6 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। कीमती धातुओं के दाम में आई इस गिरावट से उन ग्राहकों को राहत मिल सकती है, जो त्योहारों और शादी-विवाह के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं।

ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

अमेरिका में मंदिरों की सुरक्षा पर ₹100 करोड़ खर्च होंगे

इलिनॉय में मंदिर पर हमले की साजिश के बाद फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी

अमेरिका में दिवाली से पहले हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की गई है। इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। यह फैसला इलिनॉय में एक मंदिर पर हमले की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद लिया गया है। इसके तहत अमेरिका के लगभग 500 मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा में इजाफा किया जाएगा। मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे, निगरानी वाले अलार्म और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात करने की तैयारी है। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर योजना बनाई जाएगी। अमेरिका के इलिनॉय में 19 साल के अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस ने नवरात्रि के दौरान हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश

रची थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस पर 11 अक्टूबर को भारतीय मूल के लोगों की सामूहिक हत्या की योजना बनाने का आरोप था। पापोराकिस अपने घर से करीब 65 किमी गाड़ी चलाकर ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) मंदिर पहुंचा था। छुट्टी के दिन इस मंदिर में 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। वह अपने साथ राइफल और सैकड़ों गोलियां लेकर आया था, लेकिन राइफल जाम होने के कारण हमला नहीं कर सका। इसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा।

तमसा संकेत
tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड- 224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. 64107/96